भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी चेन्नई में करेगा

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

मणिपुर में पीएम मोदी का स्वागत करने को उत्सुक दिखी जनता

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 259 | रायपुर | रविवार 14 सितंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाल-बाल बचे, हॉट एयर बैलून में लगी आग

मंदसौर एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ शनिवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वह मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य में हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे, जहां उनके बैलून में अचानक आग लग गई।घटना के वक्त मुख्यमंत्री बैलून के अंदर ही मौजूद थे, लेकिन समय रहते उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें तुरंत बाहर निकाल लिया। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के मुताबिक, गांधी सागर अभयारण्य हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां हॉट एयर बैलून की सवारी करने पहुंचे थे। बैलून में बैठते ही उसके निचले हिस्से में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आग लग गई। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से स्थिति को तुरंत संभाल लिया गया और मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई 3 ट्रेनों को हरी झंडी

पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम

नई दिल्ली संवाददाता।

आइजोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है। मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक दिन, क्योंकि यह भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने तीन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुई है। यह केंद्र सरकार की विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह रेल लाइन एक चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में बनी है। इसके लिए जटिल भौगोलिक स्थितियों के तहत 45 सुरंगें बनाई गई हैं। इसमें 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वे मिजोरम के लिए निकले थे। हालांकि, दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण वे आइजोल नहीं पहुंच पाए। इसके बाद मिजोरम एयरपोर्ट पर ही उन्होंने वर्चुअली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिजोरम भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह राष्ट्र के लिए, विशेषकर मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अब आइजोल भारत के रेलवे मानचित्र पर होगा।

पीएम मोदी ने कहा, कुछ साल पहले मुझे आइजोल रेलवे लाइन की आधारशिला रखने का अवसर मिला था और आज हम इसे देशवासियों को समर्पित करते हुए गर्व महसूस करते हैं। दुर्गम भूभाग सहित कई चुनौतियों को पार करते हुए बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन एक वास्तविकता बन गई है। हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह ने इसे संभव बनाया है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहली बार मिजोरम का सैरांग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सीधे जुड़ेगा। यह सिर्फ एक रेलवे नहीं है, बल्कि परिवर्तन की जीवनरेखा है। यह मिजोरम के लोगों के जीवन और आजीविका में क्रांति लाएगी। मिजोरम के किसान और व्यवसाय देश भर के ज्यादा बाजारों तक पहुंच पाएंगे। लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। इस विकास से कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मणिपुर में सड़क पर मिले प्यार को देख हुए भावुक, हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय हिंसा भड़कने के लगभग सवा साल बाद आज, शनिवार को पहली बार मणिपुर पहुंचे। यहां भारी बारिश के कारण जब उनका हेलिकॉप्टर नहीं उड़ सका, तो उन्होंने 65 किलोमीटर का सफर सड़क मार्ग से तय कर हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान सड़क पर लोगों का अभूतपूर्व प्यार देखकर पीएम मोदी भावुक हो गए और कहा कि अच्छा हुआ आज उनका हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा। शनिवार को जब प्रधानमंत्री मोदी इंफाल एयरपोर्ट पर उतरे, तो भारी बारिश हो रही थी। अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर जाना संभव नहीं है। सूत्रों के अनुसार, इस पर पीएम मोदी ने तुरंत फैसला किया कि चाहे कितना भी समय लगे, वह सड़क मार्ग से ही जाएंगे क्योंकि उन्हें हर हाल में हिंसा पीड़ितों से मिलना है। इसके बाद वह 65 किलोमीटर का सफर करीब डेढ़ घंटे में तय कर चूड़ाचांदपुर पहुंचे और राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की।

'मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा रत्न', इंफाल में बोले पीएम मोदी

मोदी ने मणिपुर में शांति के संदेश के साथ ही 8,500 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान

मणिपुर के लोगों के जज्बे को सलाम,भारत सरकार आपके साथ है : पीएम मोदी

संवाददाता।

प्रधानमंत्री मोदी का चुराचांदपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने शहर के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना शामिल हैं; 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं; मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावास सहित अन्य।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ...मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं। थोड़ी देर पहले इसी मंच से करीब 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स मणिपुर के लोगों की, यहां हिल्स पर रहने वाले ट्राइबल समाज की जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने जल, बिजली, सड़क, शिक्षा और जनसुविधाओं वाली योजनाएं शुरू की

नई दिल्ली एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा में बिजली, पानी, सड़क और जनसुविधाओं से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जनता को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है और आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, वे दिल्ली के विकास को नई गति और दिशा प्रदान करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये परियोजनाएं केवल शालीमार बाग ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के लिए एक नई शुरुआत है। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आशीष सूद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। शालीमार बाग क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति और बिजली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जिनमें शालीमार बाग के सीए ब्लॉक और बीडब्ल्यू ब्लॉक में करीब 65 लाख रुपये की लागत से नए अंडरग्राउंड रिज़रवॉयर (यूजीआर), नए ट्यूबवेल और ऑनलाइन बूस्टर पंप शामिल हैं।

असम में बोले मोदी- भूपेन दा भारत की एकता और अखंडता के महानायक थे

एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में है. प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी 'भारत रत्न भूपेन हज़ारिका' का विमोचन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका के सम्मान में 'स्मारक सिक्का' जारी किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही 8 सितंबर को भूपेन हजारिका का जन्मदिवस बीता है. इस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी. मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में मुझे शामिल होने का अवसर मिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूपेन दा भारत की एकता और अखंडता के महानायक थे. दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था. तब भूपेन दा उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को आवाज देते रहे. उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था, उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे।

आपदाग्रस्त हिमाचल की सहायता के लिए भाजपा शासित राज्यों का आभार : अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला ,पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत भाजपा शासित राज्यों से मिली मदद पर वहाँ की जनता व मुख्यमंत्रियों का आभार प्रकट करते हुए इसे मानवता की सच्ची मिसाल बताया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा देवभूमि हिमाचल अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहा है और पिछले कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हिमाचल भ्रमण कर पीड़ितों का हाल भी जाना और देवभूमि के ज़ख्मों पर मरहम स्वरूप 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता भी दी। यह देखना सुखद है कि देवभूमि हिमाचल की आपदा में सहायता के लिए भारतीय जनता पार्टी की कई राज्य सरकारें बढ़-चढ़ कर अपनी भूमिका निभा रही हैं।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत का लोकतंत्र और जीवंत संविधान दुनिया के लिए मार्गदर्शक : लोक सभा अध्यक्ष

एजेंसी

11वां सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन राज्यपाल के सम्बोधन के साथ बेंगलुरू में सम्पन्न

पीआईबी

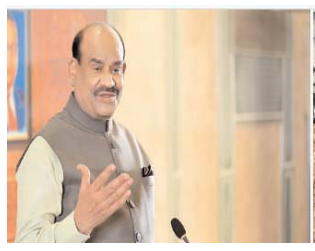

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज इस बात पर जोर दिया कि सभी विधानमंडल अपनी कार्यवाही और चर्चा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक स्थापित करें। सदनों में नियोजित गतिरोध पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि सदन में तथ्यपरक, सारगर्भित चर्चा करने वाले जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को प्रमुखता से दिखाए, ताकि सदस्यों के बीच स्वस्थ संवाद के लिए प्रतिस्पर्धा हो। लोक सभा अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानमंडल की मेज़बानी में आयोजित 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए)-भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन समारोह में ये विचार व्यक्त किए। श्री बिरला ने कहा कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में विधानमंडल नियोजित गतिरोध के बिना कार्य कर सकें।

यूएन

, 142 देशों ने पक्ष में डाला वोट, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच नई दिशा

भारत ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन प्रस्ताव का किया समर्थन

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी - संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राष्ट्र व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर पेश न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को भारत ने समर्थन देकर ऐतिहासिक कदम उठाया. यह वही भारत है जिसने पिछले तीन वर्षों में गाज़ा संघर्षविराम से जुड़े चार प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाई थी. ऐसे में भारत का समर्थन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम माना जा रहा है।

फ्रांस और सऊदी अरब की ओर से सह-प्रायोजित इस प्रस्ताव को 142 देशों का समर्थन मिला, जबकि केवल 10 देशों ने इसका विरोध किया और 12 ने मतदान से दूरी बनाई. दक्षिण एशिया, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में भारत अब तक गाज़ा पर प्रस्तावों से दूर रहा था, लेकिन इस बार वोटिंग पैटर्न बदलकर उसने साफ संकेत दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय आम सहमति के साथ खड़ा है.

भारी वैश्विक समर्थन और सीमित विरोध न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक से समर्थन मिला. इसके खिलाफ वोट देने वालों में इज़राइल, अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे और टोंगा शामिल रहे।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसे ÷शांति की ओर अपरिवर्तनीय कदम÷ करार दिया और घोषणा की कि 22 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाले उच्चस्तरीय सम्मेलन में फ्रांस औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देगा. माल्टा, कनाडा और ब्रिटेन जैसे कई यूरोपीय देशों ने भी सशर्त मान्यता देने के संकेत दिए हैं.

प्रस्ताव का रोडमैप सात पन्नों का यह डिक्लेरेशन एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है जिसमें ठोस और समयबद्ध कदम तय किए गए हैं।

नेपाल में अगले संसदीय चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे

एजेंसी -

नेपाल में राष्ट्रीय चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के कार्यालय ने घोषणा की है कि अगले संसदीय चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे। नेपाल में बीते कुछ दिनों से चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार नई सरकार (अंतरिम) ने अपना कार्यकाल संभाल लिया है. नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है. वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं. सुशीला कार्की के शपथग्रहण कार्यक्रम में सुदन गुरुंग समेत तमाम युवा नेता मौजूद रहे. नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने में सुदन गुरुंग का भी अहम योगदान है. सुशीला कार्की के शपथग्रहण समारोह के बाद जो तस्वीरें सामने आई उसमें सुदन गुरुंग सुशीला कार्की का आशीर्वाद लेते दिख रहे हैं. इस तस्वीर से इतना तो साफहै कि नए नेपाल की स्थापना में सुशीला कार्की और सुदन गुरुंग अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं. लोग सुदन गुरुंग के बारे में जरा विस्तार से जानने को उत्सुकता हैं.

सुदन गुरुंग एक युवा नेता हैं. आज की तारीख में उन्हें नेपाल के युवाओं की आवाज माना जा रहा है. बीते दिनों नेपाल में केपी ओली सरकार को सत्ता से बेदखल करने में सुदन गुरुंग और उनके समर्थकों का बड़ा योगदान था. दरअसल, इस प्रदर्शन की शुरुआत ओली सरकार के उस फैसले के खिलाफ हुई थी जिसमें सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था.इस फैसले के आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया. 36 साल के सुदन गुरुंग ही इस संगठन के लीडर हैं. सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है.

सुदन गुरुंग के एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ है. इसमें इन्हें सोशल एक्टिविस्ट बताया गया है. गुरुंग का संगठन नेपाल में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं और तमाम तरह की कठिनाइयों में मदद करने का दावा करता है. गुरुंग का ये संगठन युवाओं में काफी पॉपुलर है, यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आए.

कार्की के नेपाल की अंतरिम पीएम बनने पर भारत ने जताई खुशी

आपको बता दें कि सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता की कमान मिलने पर भारत ने भी खुशी जताई है. नई दिल्ली की तरफसे कहा गया है कि हम सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनाए जाने का स्वागत करते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में अब शांति और स्थिरता का माहौल कायम होगा.करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साथी, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पार्टनर होने के नाते भारत दोनों देशों की भलाई और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेगा।

जिनेवा प्रदर्शनी में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी उत्पीड़न पर प्रकाश डाला

संवाददाता।

जिनेवा ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिफेंस (जीएचआरडी) द्वारा जिनेवा में ब्रोकन चेयर स्मारक के बगल में प्रतिष्ठित प्लेस डेस नेशंस में आयोजित एक प्रदर्शनी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में कमजोर अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जा रहे उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। 8-10 सितंबर तक चले तीन दिवसीय कार्यक्रम ने आम जनता, सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का काफी ध्यान आकर्षित किया। प्रभावशाली पोस्टरों, सांख्यिकीय साक्ष्यों और पीड़ितों के चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी ने पाकिस्तान में अहमदिया, सिंध और बलूच समुदायों के साथ-साथ बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद किया, जिन्हें अक्सर चुप करा दिया जाता था या नजरअंदाज कर दिया जाता था। जीएचआरडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ये समूह व्यवस्थित भेदभाव, लक्षित हिंसा, जबरन धर्मांतरण, अपहरण और धर्म या आस्था की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का सामना करते रहते हैं। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के सदस्यों को कानूनी रूप से मताधिकार से वंचित किया जाता है और अक्सर नफरत भरे अभियानों का शिकार होना पड़ता है, जबकि बलूच और सिंधी कार्यकर्ता अक्सर जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं का शिकार होते हैं। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को धमकी, पूजा स्थलों के विनाश और राजनीतिक व सामाजिक जीवन में हाशिए पर धकेले जाने का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिः बस्तर को मिला पहला 350 बेड का निजी अस्पताल

रायपुर । जगदलपुर में पहली बार 350 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए रायपुर स्टोन क्लिनिक प्रा. लि. को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किया गया है। 550 करोड़ रुपये के निवेश और 200 रोजगार अवसरों के साथ यह परियोजना बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाई देगी और इसे मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाएगी। बता दें कि बस्तर आज विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र–उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन–में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रही है। यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की गाथा

लिख रहा है।

इसके अतिरिक्त, जगदलपुर में 33 करोड़ रुपये के निवेश से एक और मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल तथा नवभारत इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 85 करोड़ रुपये के निवेश से 200 बेड का मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। ये पहल न केवल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगी, बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी।

खाद्य प्रसंस्करण में नई शुरुआत

बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव में आधुनिक राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए अनेक रोजगार अवसर सृजित होंगे।

एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन

नारायणपुर जिले में पार्श्वा एग्रीटेक प्रतिवर्ष 2,400 टन परबॉयल्ड चावल का उत्पादन करेगी। 8 करोड़ रुपये के निवेश और नए रोजगार के साथ यह परियोजना बस्तर की कृषि उपज को वैल्यू एडिशन का नया आधार देगी।

वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रगति

जगदलपुर में नमन् क्लब एंड वेलनेस सेंटर 7.65 करोड़ रुपये के निवेश और 30 रोजगार अवसरों के साथ स्थापित हो रहा है। वहीं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।

डेयरी और कृषि-आधारित उद्योग

बस्तर डेयरी फार्म प्रा. लि. 5.62 करोड़ रुपये का निवेश कर दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को गति देगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

निर्माण सामग्री और औद्योगिक विकास

पीएस ब्रिक्स और महावीर माइन्स एंड मिनरल्स जैसी कंपनियाँ ईंट और स्टोन क्रशर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जिससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचा सशक्त होगा।

वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज

कांकेर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव में नए वेयरहाउसिंग केंद्र स्थापित हो रहे हैं। दंतेश्वरी कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाएँ किसानों की उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, बर्बादी घटाने और लाभ बढ़ाने में मदद करेंगी।

छत्तीसगढ़ के बड़े संस्थानों पर (ईपीएफओ) की सख्ती, 11 करोड़ से अधिक बकाया वसूली के आदेश

रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य के चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की है। भविष्य निधि अधिनियम का अनुपालन न करने वाले इन संस्थानों पर कुल 11 करोड़ 24 लाख 90 हजार 875 रुपये की देनदारी बकाया पाई गई है।

जारी सूची में दुर्ग स्थित बीएसआर सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड पर 6 करोड़ 1 लाख से अधिक, रायपुर की आइडियाक इंक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 1.34 करोड़, रायगढ़ के किरोडीमल प्रौद्योगिकी संस्थान पर 1.01 करोड़ तथा दुर्ग की प्रतिभा फ्लोकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 38 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि दर्ज है। इसी प्रकार रायपुर की नवभारत फ्यूज कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, डीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भिलाई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग की आसिया फैब्रिकेटर्स और रायगढ़ की कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी लाखों रुपये की चूक पाई गई है।

(ईपीएफओ) ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली के लिए संगठन द्वारा अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत बैंक खाते अटैच करने, संपत्ति कुर्क करने से लेकर नियोक?ता की गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुसार, इस वर्ष अब तक 65 संस्थानों के बैंक खाते अटैच कर करीब 49 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

कार्यालय प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री जयवदन इंगले ने जानकारी दी कि बकाया वसूली के लिए प्रवर्तन अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जिन्हें गहन जांच और वसूली का जिम्मा सौंपा गया है।

तारलागुड़ा और तीमेड़ के रेत खदान में NGT के नियमों का हो रहा घोर उल्लंघन : नीना रावतिया उद्दे

भाजपा नेता बी. गौतम राव के अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की हो जाँच - नीना रावतिया उद्दे

बीजापुर । बीजापुर जिले के तारलागुड़ा और तिमेड़ में अवैध रेत उत्खनन, भंडारण और परिवहन को लेकर जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमति नीना रावतिया उद्दे ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस मामले में दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

नीना रावतिया उद्दे ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि भाजपा नेता और कथित रेत ठेकेदार बी. गौतम राव द्वारा किए जा रहे अवैध रेत खनन से जिले के खनिज राजस्व और रॉयल्टी को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर ज़िला पाँचवी अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस ज़िले में पेशा क़ानून लागू है बावजूद इसके बिना ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अनुमति के बगैर अवैध भोपालपट्टनम क्षेत्र के तारलागुड़ा और तीमेड़ इलाके में अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन कथित रेत ठेकेदार और भाजपा नेता बी. गौतम राव द्वारा किया जाना गंभीर अपराध है यह सब बिना सरकार और प्रशासन के संरक्षण के संभव नहीं है जिसकी जाँच किया जाना आवश्यक है ।

उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम राव को जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण एक रॉयल्टी पर्ची पर दो-तीन ट्रकों से रेत का परिवहन किया जा रहा है, और इसकी जांच नहीं हो रही। यह गतिविधि भोपालपटनम क्षेत्र से महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में रेत के अवैध परिवहन को बढ़ावा दे रही है, जिससे नियमों का उल्लंघन और राजस्व की चोरी हो रही है। नीना रावतिया ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, ताकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके।नीना ने अपने विज्ञप्ति में यह भी कहा कि पर्यावरणीय नुकसान के संदर्भ में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (ह्लत्रञ्ज) ने अवैध रेत खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुआवजा लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नीना रावतिया और अन्य नेताओं ने इस मामले में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई की मांग की है, ताकि जिले के प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोका जा सके और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो। नीना रावतिया ने यह भी कहा कि तारलागुड़ा एवं तीमेड़ में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में कॉग्रेस पार्टी ज़िले के लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी।

अवैध शराब तस्करी के 10 मामलों में 10 लोगों पर कार्यवाही

राजनांदगांव । जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के दस अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 08 आरोपियों से 278 पौवा देशी शराब एवं 151 पौवा अंग्रेजी शराब जप्त किया है।

बता दें कि पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के पर्यवेक्षण में दिनांक 12.09.2025 को अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। जिसपर थाना डोंगरगढ़, कोतवाली, बसंतपुर, ओ.पी. चिखली और चिचोला द्वारा 34(2) एवं 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् 05 प्रकरण में 05 आरोपियों के कब्जे से 226 पौवा देशी शराब किमती 20270/-रू. व बिक्री रकम 5170/- रू0, 151 पौवा अंग्रेजी शराब किमती 18360/- रू0 बरामद किया गया तथा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत् 03 प्रकरण में 03 आरोपियों के कब्जे से 52 पौवा देशी शराब किमती 4340/- रू. व बिक्री रकम 380/- रू0 बरामद कर जुमला किमती 48540/- रू0 जप्त किया गया, साथ ही ओ.पी. मोहारा एवं तुमड़ीबोड़ द्वारा 36(च) के तहत 01-01 कार्यवाही की गई आरोपियों को जेल भेजा गया।

बीसीसीआई के साथ एमओयू करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है – अरुण साव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बस्तर के विकास से कोई सरोकार नहीं है - उप मुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि, बस्तर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि, दीपक बैज बस्तर का विकास नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि बस्तर में तरक्की आए। श्री साव ने कहा कि, दीपक बैज को तरक्की और विकास से कोई नाता नहीं है। बस्तर तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया बस्तर की ओर आकर्षित हो रही है। साय सरकार में बस्तर की दिशा बदल रही है। विकास की सौगात बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। इससे कांग्रेसियों को तकलीफ हो रही है। आदिवासियों का विकास उनसे देखा नहीं जा रहा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जापान प्रवास से आने के बाद तत्काल बस्तर में बाढ़

का जायजा लेने गए, मंत्री और अधिकारी भी लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, खेल विभाग का नवीन दायित्व मिलने के बाद खेल से जुड़े प्रतिनिधि मिलने पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनसे खेलों और खिलाड़ियों के विकास पर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की है। नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। और बीसीसीआई के साथ एमओयू करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

महिला बाल विकास मंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधित विभागीय संस्थाओं में व्यवस्थाओं का किया

आवासीय संस्थाओं में भोजन, शयन आदि व्यवस्थाओं का किया अवलोकन

जशपुरनगर । महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने सरगुजा संभाग के दौरे पर शुक्रवार को जशपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने सर्वप्रथम शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह बालक का निरीक्षण किया। जहां उन्होंने विधि से संघर्षरत बालकों हेतु रहने, भोजन, बिस्तर, सीसीटीवी, पेयजल आदि की व्यवस्था की जांच की। जहां एक विधि से संघर्षरत बालक से मुलाकात कर उन्होंने उसे पढ़ाई एवं अच्छा आचरण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्था की पंजी की जांच की एवं काउंसिलिंग व्यवस्था का भी मुआयना किया। उन्होंने बाल कल्याण समिति एवं

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों से भी मुलाकात की।इसके पश्चात उन्होंने बालिका बाल गृह का निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने निवासरत बच्चों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। बच्चों ने अपनी दिनचर्या बताई। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने भोजन कक्ष का निरीक्षण कर भोजन की जांच की। उन्होंने रसोइयों से चर्चा कर खाने के समय और मीनू पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने नियमित सफाई करवाने के निर्देश दिए।

बालिकाओं हेतु खुला आश्रय गृह पहुंच कर उन्होंने बच्चों के मनोरंजन एवं काउंसिलिंग व्यवस्था की जांच की। इसके उन्होंने वसुंधरा विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी का निरीक्षण किया। जहां छोटे छोटे बच्चों को देखकर उनके मन में वात्सलय उमड़ पड़ा उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा उनके संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में बच्चों के लिए लगाए गए पालनों और बच्चों के भोजन व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पालनों को पूर्ण रूप से कव्हर करने को कहा। उन्होंने महिलाओं की सहायता के लिए संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंच सेंटर में आई महिलाओं से चर्चा की और उनकी परेशानी को भी जाना। एक पीड़िता के पति की मृत्यु उपरांत घर से निकाले जाने की समस्या सुनकर उन्होंने उन्हें सहायता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं के प्रति संतुष्टि जाहिर करते हुए नवा बिहान एवं काउंसिलिंग कक्ष का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव, संयुक्त संचालक श्रीमती अर्चना राणा सेठ, डीपीओ श्री अजय शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री समीर बड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

विधायक गोमती साय ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार–प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

यह रथ पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शहरों और गांवों में भ्रमण कर लोगों को योजना की देगा जानकारी

जशपुरनगर। विधायक एवं सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष श्रीमति गोमती साय ने अपने निज निवास स्थान ग्राम मुण्डाडीह में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार-प्रसार रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ पत्थलगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शहरों और गांवों में भ्रमण कर लोगों को योजना की जानकारी देगा और इसके लाभों से अवगत कराएगा। इस अवसर पर श्री उपेन्द्र साय, श्री आकाश पारिक सहित अनेक जन प्रतिनिधी ग्रामीण जन एवं विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक श्रीमती साय ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। इस योजना के अन्तर्गत 01 से 03 किलो वॉट तक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित कर हर महिने 100 से 360 यूनिट तक बिजली उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत् 01 किलोवॉट सोलर प्लांट लगाने पर केन्द्र सरकार की ओर से 30 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 15 हजार की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह 02 किलोवॉट सोलर प्लांट लगाने पर केन्द्र सरकार की तरफ से 60 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी और 03 किलोवॉट सोलर प्लांट लगाने पर केन्द्र सरकार की तरफ से 78 हजार तो राज्य सरकार की तरफ से 30 हजार की सब्सिडी मिलती है। इस योजना अन्तर्गत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को बैंक के द्वारा 6 प्रतिशत दर पर आसान किस्तों में 10 वर्षों के लिए ऋण की सुविधा दी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता द्धह्लह्लश्चह्य=//श्चद्वह्यह्वह्म4ड्डद्दद्धड्डह्ल.द्दश1.द्बठ्ठ पीएम सूर्य घर मोबाईल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप अथवा टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक उपभोक्ता नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

बस्तर में पर्याप्त संसाधन हैं। उद्योग लगाने पर कच्चे माल की लागत कम होगी

रायपुर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के उद्यमशील युवाओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से पूंजी, स्किल और काउंसलिंग दी जा रही है। इसके चलते नया उद्यमी वर्ग तेजी से उभर रहा है। बस्तर में पर्याप्त संसाधन हैं। उद्योग लगाने पर कच्चे माल की लागत कम होगी। पोर्ट सिटी से कनेक्टिविटी है, निर्यात में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि औद्योगिक नीति में जो विपुल प्रोत्साहन हैं उनका लाभ उठाने का यह स्वर्णिम अवसर है। बस्तर ने निवेश के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है और विकास के लिए टेकऑफकरने वाला है। आप सभी बस्तर की सफ्लता की इस उड़ान में शामिल हों। बस्तर में निवेश करें, यहाँ निवेश का भविष्य बेहद उज्ज्वल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए आकर्षक और लाभकारी साबित हो रही है। अब तक 6.95 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि बस्तर में अधिक से अधिक निवेश होने से यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आईटी सेंटर सहित अन्य अधोसंरचना विकसित की गई है और उद्योगों को अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर में पहली बार राइस मिल की स्थापना हो रही है। उन्होंने बताया कि जगरगुंडा की इमली मंडी, जो वर्षों से बंद थी, को फ्रि से चालू कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक नीति की सराहना दक्षिण कोरिया में भी हुई है, जिससे छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर नई पहचान मिली है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार ने वीडियो प्रजेंटेशन के माध्यम से राज्य की औद्योगिक नीति और बस्तर संभाग में उभरती संभावनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बस्तर की समृद्धि के लिए पर्यटन और छोटे उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साल बीज और इमली जैसे उत्पादों की देशव्यापी आपूर्ति में बस्तर की प्रमुख भूमिका है, जिनका उपयोग कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है। उन्होंने बताया कि निवेशकों के लिए औद्योगिक माहौल को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई नवाचार किए गए हैं। अब उद्यमियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और साल में केवल एक बार परीक्षण होगा।

पंडित लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज सारंगढ़ में हुआ रजत जयंती संगोष्ठी का आयोजन

छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस भविष्य एवं चुनौतियां'' विषय पर वक्ताओं ने किया संबोधन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना उत्सव पर्व पर सारंगढ़ के शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय कॉलेज में ''छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस भविष्य एवं चुनौतियां'' विषय पर रजत जयंती संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस समारोह में अतिथि के रूप में कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, विधायक उत्तरी जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, सदस्य विनोद भारद्वाज, गणमान्य नागरिक ज्योति पटेल, हरिनाथ खूंटे, ताराचंद देवांगन, सूर्यकांत तिवारी, सरिता गोपाल, पत्रकार गोल्डी नायक, दीपक थवाईत, कॉलेज के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्राचार्य लोकेश पटेल, सहायक प्राध्यापक डॉ. टंकेश्वरी और अदिति तलवरे पटेल, रामचंद्र भैना सहित कॉलेज के अन्य प्रोफेसर, एनसीसी, एनएसएस आदि के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने इस अवसर पर कहा कि ई-गवर्नेंस अंतर्गत लोक सेवा गारंटी के तहत जाति, निवास, जन्म, मृत्यु आदि प्रमाण पत्र आदि बुनियादी सभी कार्य किए जा रहे हैं। पढ़ाई को जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प और शॉर्टकट नहीं है। मेहनत निश्चित ही करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, अनिच्छा होने के बाद भी सफ्लता के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पान, पानी और पालगी की यह धरती सारंगढ़ प्रतिभा की धनी है। यहां के आईएएस शरदचंद्र बेहार ने मध्यप्रदेश में मुख्य सचिव और आईपीएस विजयशंकर चौबे ने छत्तीसगढ़ के एडीजीपी जैसे

विधायक उत्तरी जांगड़े ने कहा कि मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने पर सभी छत्तीसगढ़िया को लाभ हुआ है। सभी अच्छा से पढ़ाई करें, सीखते रहें, जीवनभर हमें कुछ न कुछ हमेशा सीखना पड़ता है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लें और जो योजना के बारे में नहीं जानते उन्हें बताएं और लाभ दिलाने में मदद करें।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने अपने वादा को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। हमारा राज्य विकसित है। आप सभी सपने देखे, सपने ऊंचा रखें, चुनौतियों से धबराना नहीं है। सत्ताधारी दल के जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण वाजपेयी जी की देन है। आप सभी केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लें। सभा को मनोज जायसवाल, गोल्डी नायक, अतुल पटेल, अंकित भोई, आर.के. पिवहरे, पंकज साहू, डॉ. माया पारस आदि ने संबोधित किया।

वक्ता के रूप में प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी देवराम यादव ने कहा कि राज्य स्थापना का जो रजत जयंती हम मना रहे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की देन है। आज जमाना टेक्नोलॉजी का है।

महतारियों के सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ सरकार ने कायम की मिसाल

लोकशक्ति, रायपुर। स्त्री पुरुष समानता के मामले में छत्तीसगढ़ की मिसाल पूरे देश में रही है लेकिन आर्थिक समानता में फिर भी पुरुषों का पलड़ा अब तक भारी होता था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की सरकार आने के बाद इस आर्थिक विषमता को दूर करने का रास्ता भी खुल गया है। अब छत्तीसगढ़ की हर माँ और बहन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए वे स्वयं निर्णय ले सकती हैं। महतारी वंदन योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को उनके श्रम और भागीदारी के लिए सम्मानित करती हैं वहीं साय सरकार की आजीविकामूलक योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की राह मिली है। आधी आबादी को सशक्त कर मुख्यमंत्री ने विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला रख दी है।

छत्तीसगढ़ ने पिछले 19 महीनों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और त्वरित लाभ पहुंचाने की व्यवस्था स्थापित की गई है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। 1 मार्च 2024 से लागू इस महत्वाकांक्षी योजना ने राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में क्रांति ला दी है। विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जा रहे हैं।मार्च 2024 से सितम्बर 2025 तक 69.15 लाख से अधिक महिलाओं को 12,376.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।यह राशि महिलाओं की आत्मनिर्भरता, पोषण और मूलभूत जरूरतों की पूर्ति में सहायक है।चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 5, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।179 महतारी सदन के निर्माण के लिए 52.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक सदन 2,500 वर्गफुट में 29.20 लाख रुपए की लागत से बनेगा, जो महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, बैठक और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र होगा।साय सरकार ने महिला श्रमिकों और स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं: जिसमें मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को 7,900 रुपए की सहायता एक सिलाई मशीन के लिए दी जा रही है।दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से 3 वर्ष से पंजीकृत महिला श्रमिकों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है।मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके।मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना ने पंजीकृत श्रमिकों को अपनी 18-21 वर्ष की अविवाहित पुत्रियों के पढ़ाई लिखाई तथा अन्य आवश्यक खर्चों के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी साय सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से उन्हें बिना जमानत के 25,000 रुपए का ऋण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।सक्षम योजना ङ्क 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को ३त्न ब्याज पर 2 लाख रुपए तक ऋण भी दिया जा रहा है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) ङ्क 800 करोड़ रुपए का प्रावधान, ÷लखपति महिला÷ और ÷ड्रोन दीदी÷ जैसी नवाचारी पहलें भी योजनाओं में शामिल है।इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ, उन्हें रोजगार के स्थायी अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। नवाबिहान योजना से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा, परामर्श और आश्रय सुविधा प्रदान की जाती है।इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।छत्तीसगढ़ सखी वन-स्टॉप सेंटर में स्ह्वक्र लागू करने वाला देश में पहला राज्य बन गया है। 27 जिलों में सेंटर संचालित, 24×7 सेवा उपलब्ध है।महिला हेल्पलाइन 181 और डायल 112 द्वारा संकट में फंसी महिलाओं को त्वरित सहायता और पुलिस समन्वय की सुविधा प्रदान की जाती है।

रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट काउंटर अब आरक्षण केंद्र के भीतर होंगे, प्रक्रिया शुरू

रायपुर । रायपुर रेलवे स्टेशन में अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र के अंदर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और सुव्यवस्थित सेवा प्रदान करना है। आने वाले कुछ दिनों में यात्रियों को जनरल टिकट अब आरक्षण केंद्र के अंदर से ही मिलेंगे।

यात्रियों को इस बदलाव के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे का वाणिज्य विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। स्टेशन पर भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिसमें विभागीय अधिकारी, निरीक्षक और सुपरवाइजर जुटे हुए हैं। फिलहाल एक टिकट काउंटर को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके स्थान पर तीन अतिरिक्त ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगाई गई हैं और चार कर्मचारियों को मोबाइल टिकट सेवा देने के लिए तैनात किया गया है। अगले 24 घंटों में एक और एटीवीएम को शिफ्ट किया जाएगा, जबकि 48 से 72 घंटों के भीतर शेष सभी अनारक्षित टिकट काउंटरों को आरक्षण केंद्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यात्रियों की सुविधा बनाए रखने के लिए वाणिज्य विभाग का कंट्रोल रूम लगातार हर घंटे हालात की निगरानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, 24 घंटे कार्यरत मुख्य वाणिज्य निरीक्षक और चीफ सुपरवाइजर स्टेशन पर मौजूद हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और अपने अधिकारियों के साथ हर घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं

नवीन मार्केट परिसर को एक बहुद्देशीय एवं आधुनिक वाणिज्यिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा

कार्यकर्ताओं,नागरिकों,विभिन्न समाजों ने मनाया भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू का जन्मदिन

0 कारगिल योद्धाओं एवं सेना में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षित करने वाले पूर्व सैनिकों का किया सम्मान

0 मजदूरों का भी हुआ सम्मान,रंजना साहू दीर्घायु हों के लगते रहे नारे

0 उपस्थित जनसैलाब का धमतरी की नेता के प्रति स्नेह देखते बन रहा था

धमतरी, - भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रंजना साहू का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं,नागरिकों,व्यापारियों,समाजप्रमुखों द्वारा स्थानीय घड़ी चौक में धूमधाम से मनाया गया,वहीं उक्त अवसर पर रंजना साहू ने कारगिल युद्ध में धमतरी से भाग लेने वाले उस वक्त के कारगिल योद्धाओं का सम्मान किया एवं युवाओं को सेना में चयनित कराने निशुल्क प्रशिक्षण देने वाले पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया एवं उनके द्वारा मजदूरों का भी सम्मान किया गया,सम्मान पाकर भावविभोर होकर मजदूरों ने रंजना साहू दीर्घायु हो के नारे लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया,उपस्थित जनसैलाब का धमतरी की नेता के प्रति अपार स्नेह और अपनत्व देखते बन रहा था।प्रातः श्रीमती साहू ने हनुमान मंदिर,विंध्यवासिनी मंदिर,शीतला माता मंदिर,अंगारमोती माता मंदिर,रुद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंच कर आशीर्वाद लिया उसके पश्चात घड़ी चौक में धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया,उक्त अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री राकेश साहू,भाजपा कोषाध्यक्ष चेतन हिंदुजा,विजय साहू,न.नि एम.आई.सी सदस्य नरेंद्र रोहरा, विजय मोटवानी, निलेश लूनिया,पार्षद कोमल सार्वा, घड़ी चौक व्यापारी संघ के अध्यक्ष ज्ञानचंद लूनावत, राजेश पंजवानी, अशोक नंदा, आसानदास जेठवानी, ललित बरडिया, संजू लुंकड़, रोहित वाधवानी, अभिषेक हिरानी, रमेश लुंकड़, अखलाख हाशमी, कल्याणदास मलवानी, चंदू जसवानी, महेश रामरख्यानी, अमर पिंजानी, अशोक वाधवानी, अशोक दुंबा, दिलीप पटेल, भरत सोनी, दयाशंकर सोनी, विनोद रणसिंह, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष देवेश अग्रवाल, महामंत्री जय हिंदुजा, रिक्की गनवानी सूरज शर्मा ।

कांकेर लोकसभा सीट पर चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, सांसद भोजराज

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दायर चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया खारिज करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका में प्रस्तुत तथ्यों और आरोपों के आधार पर यह मामला सुनवाई योग्य है।

यह याचिका कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर द्वारा 18 जुलाई 2024 को दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कांकेर लोकसभा क्षेत्र में मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम रद्द करने, कुछ मतदान केंद्रों पर पुनः मतगणना और 15 केंद्रों पर दोबारा मतदान की मांग की है। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी, वोटिंग डेटा के ट्रांसमिशन में देरी और मतगणना प्रक्रिया में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।

सांसद की आपत्ति को कोर्ट ने किया खारिज

सांसद भोजराज नाग ने अपनी अंतरिम अर्जी में यह तर्क दिया था कि याचिका में भ्रष्ट आचरण से संबंधित कोई ठोस आरोप नहीं है और यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 81, 82 और 83 के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है और याचिका वकील के माध्यम से दाखिल की गई है, जो नियमों का उल्लंघन है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि याचिका विधिसम्मत तरीके से दाखिल की गई है, सभी पत्रों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं। साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाना अनिवार्य नहीं है और याचिका सभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार है।

अगली सुनवाई 3 नवंबर को

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी, ईवीएम से छेड़छाड़ और डेटा ट्रांसमिशन में देरी जैसे गंभीर आरोप हैं, जिनकी सुनवाई जरूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें अदालत याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच करेगी। यह मामला अब मेरिट के आधार पर सुना जाएगा, जिसमें तय होगा कि 2024 का कांकेर लोकसभा चुनाव परिणाम वैध है या नहीं।

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सियासी हलचल, उपमुख्यमंत्री ने की एसआईआर की मांग

रायपुर, बिहार और अन्य राज्यों की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत गरमा गई है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर (विशेष पुनरीक्षण) की आवश्यकता है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को विरोधाभासी बयान देने से बचना चाहिए। एक तरफवह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात करते हैं, दूसरी ओर एसआईआर पर सवाल खड़े करते हैं। अगर गड़बड़ी है, तो जांच भी होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर कराई जानी चाहिए।

गरियाबंद जिले के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है।

कृषक रजत संवाद : 69 सोसायटियों में हुआ आयोजन, किसानों को मिल रही नवीन तकनीकी जानकारी

रायपुर। किसानों को नवाचार और तकनीकी ज्ञान से अद्यतन कराने के लिए कृषक रजत संवाद आयोजित हो रहे हैं, जो अब तक 69 सोसायटियों में हुए हैं। उसमें 2339 कृषक, 525 प्रगतिशील कृषक एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह शिविर 3 सितंबर को प्रारंभ हुआ है जो 16 सितम्बर 2025 तक संचालित किए जाएंगे।

शिविर में प्रगतिशील कृषकों ने अपने अनुभव साझा कर अन्य कृषकों को प्रेरित किया। अब तक प्राप्त आवेदनों में 164 नवीन केसीसी, 155 निष्क्रिय केसीसी को सक्रिय करने हेतु, पीएम किसान सम्मान निधि के 124 एवं एग्रीस्टैक पंजीयन के 283 आवेदन शामिल हैं। इसके साथ ही योजनाओं की जानकारी देने हेतु कृषकों को व्हाट्सएप्प चैनल से भी जोड़ा जा रहा है।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि जिले के कृषक आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। शासन की सभी योजनाएँ तभी सफल होंगी जब कृषक इनसे सीधे लाभान्वित हों। इस प्रकार के संवाद शिविर कृषकों को जागरूक करने और योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम हैं÷

उप संचालक कृषि ने बताया कि आगामी दिनों में विकासखंड-धरसींवा में सड्डू, मांढर, पंडरभट्ठा, मोहदी, कुंरा, भाठागांव, उरला, सिलतरा, टाटीबंध, टेकारी, विकासखंड-आरंग में चिखली, भंडारपुरी,

फ रफैद, लखौली, भलेरा, गोईन्दा, बाना, गुल्लू, चपरीद, पंधी, जरौद, गोढ़ी, खमतराई, टेकारी, गनौद, मुनरेठी, खोरसी, कोरासी, अमसेना, देवर तिल्दा, सेमरिया, विकासखंड-अभनपुर में मानिकचौरी, परसदा, सारखी, सुन्दरकेरा, बंजारी, तोरला, टीला, पटेवा, जामगांव, बेन्द्री, सकरी, पिपरौद एवं विकासखंड-तिल्दा में टोहड़ा, सरोरा, देवरी, बिलाड़ी, सांकरा, किरना, बरतौरी, रायखेड़ा, खैरखुटा, बुडेरा, छडिया, असौंदा, मांठ, भिंभौरी, अड़सेना में आयोजित होंगे। कृषि विभाग ने कृषकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में शामिल होकर विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

रेस विज्ञप्ति 21वां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस : वनमंत्री ने वन शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

रायपुर। 21वां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर दिनांक 11/09/2025 को राजीव स्मृति वन (ऊर्जा पार्क) रायपुर में स्थित वन शहीद स्मारक में शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ द्वारा वन शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में श्री केदार कश्यप जी वन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वनमंत्री श्री केदार कश्यप जी ने कहा कि, आज भावनाओं से भरा दिन है। हम उन वीर शहीदों का स्मरण कर रहे हैं। जिन्होंने जंगलों, प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करने हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। वनमंत्री द्वारा वन शहीद के परिजनों को शॉल श्रीफल भेंट किया गया।छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री अजीत दुबे जी द्वारा कांकेर वनमण्डल ड्यूटी के दौरान भालू के हमले से मृत श्री नारायण यादव जी को वन शहीद का दर्जा दिलाने हेतु वनमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन भी सौंपा गया।

साथ ही साथ वन शहीद दिवस पर माननीय वन मंत्री जी के हाथों स्मारिका का विमोचन भी किया गया।जब राजा ने जंगल कटवाने मार दिए 363 लोग11 सितंबर 1730 को जोधपुर के खेजडी गांव में वनों को बचाने के लिए अमृता देवी और उनकी तीन बेटियों समेत 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ के साथ कटकर अपनी जान गंवा दी थी उन सभी सच्चे पर्यावरण हितैषी शहीदों एवं वन शहीदों की याद में हर वर्ष 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है।

कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु वनमंत्री जी के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) श्री व्ही श्रीनिवास राव जी, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष श्री अजीत दुबे जी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी सहित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से पहुंचे संगठन के साथी सम्मिलित रहे। उक्त आशय की जानकरी दीपक तिवारी प्रदेश महामंत्री पवन पिल्लै संगठन सचिव ने दी।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दशहरा पर्व की बैठक ली

जशपुर। विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत और कलेक्टर श्री रोहित व्यास और एस एस पी श्री शशि मोहन सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दशहरा समिति की बैठक ली कलेक्टर ने कहा कि जिले में दशहरा पर्व परंपरागत और उत्साह से मनाया जाएगा। उन्होंने समिति की मांगों के अनुरूप संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें पार्किंग, बिजली व्यवस्था, आपातकालीन स्थिति हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम व एम्बुलेंस, बेरिकेटिंग, फायर ब्रिगेड की सुविधा एवं शहर की स्वच्छता शामिल है। नगर निगम एवं जनपद सीईओ को विशेष साफसफाई करने और वन विभाग को पेड़ों की छंटाई करने के निर्देश दिए गए।

छात्र संघ चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकार

छात्र संघ गठन के लिए मनोनयन भी नहीं होगा

छात्र संघ चुनाव नहीं कराने से राष्ट्रीय दलों के छात्र संगठनों में रोष

रायपुर, 12 सितंबर (आरएनएस)। उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके कारण इस वर्ष छात्र संघ के गठन के लिए मनोनयन भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा के छात्र संगठनों ने भी चुप्पी साध ली है।

मिली जानकारी के अनुसार रविशंकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 150 महाविद्यालय हैं यहां पर छात्र संघ के चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। कुलपतियों की राय है कि छात्र संघ चुनाव कराने से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में गुण्डागर्दी और तनाव पूर्ण माहौल बना रहता है तथा यहां पर आए दिन हड़ताल की जाती है, जिससे शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होता है। इसलिए शासन ने यहां छात्र संघ चुनाव के गठन के लिए कक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर अध्यक्ष, कक्षा प्रतिनिधि चुनने का फैसला किया था, लेकिन उच्च शिक्षा संचालनालय का कहना है कि लिंगदोह कमेटी की अनुशंसा के अनुसार छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। ज्ञात रहे छात्र राजनीति से निकलकर ही छात्र नेता आगे चलकर राजनीति में आते हैं, इसके पश्चात वे नेतृत्व करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता इनका उपयोग राजनीति में बेहतर ढंग से करते हैं। एनएसयुआई एवं कांग्रेस के नेता आकाश शर्मा के अनुसार छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर हम राज्यपाल से मिलेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन दिया जाएगा। सतारूढ़ दल से संबद्ध एबीवीपी के नेताओं की चुप्पी भी रहस्यमय बनी हुई है।

संपादकीय

एमएबी में बढ़ोतरी यकीनन अप्रिय और अनुचित

आईसीआईसीआई बैंक, भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक, ने एक अगस्त या उसके बाद खोले जाने वाले नये बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की अनिवार्यता पांच गुना बढ़ा कर 50 हजार रुपये कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक बचत बैंक खातों में न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि (एमएबी) 10 हजार रुपये थी। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अर्ध-शहरी इलाकों में यह सीमा 25 हजार और ग्रामीण इलाकों में 10 हजार रुपये कर दी गई है। अलबत्ता, एक अगस्त से पहले खोले गए बचत खातों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वेतन खातों, प्रधानमंत्री जनधन खातों और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट धारकों को इस नियम से छूट मिलेगी क्योंकि ये सभी जीरो बैलेंस खाते हैं। इसके अलावा, वेतनभोगियों को भी बढ़े शुल्कों से छूट मिलती रहेगी। अरसे से बैंक में न्यूनतम राशि बनाए रखने को लेकर बैंक सेवाभोगियों की शिकायत जब-तब उठती रही है।

देश में बाढ़ से भीषण तबाही, नोएडा के कई सेक्टर बाढ की चपेट में आने का मतलब,

अजय दीक्षित

मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि पूरे सितंबर 2025 में विशेषकर उत्तर भारत, हिमालय, और पश्चिमी घाट से लगे क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। अभी पूरे देश में बारिश के नदियों, गंगा, जमुना, और छोटी मोटी नदियों में आए पानी से संपूर्ण उत्तर भारत में बाढ़ आ गई है वह भी इतनी भीषण है कि दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर गया है। नोएडा सरीखी अत्याधुनिक कॉलोनी में कई सेक्टरों

पानी भर गया है स्कूल कॉलेज, ऑफिस बंद कर दिए हैं। यमुना नदी का पानी का जल स्तर खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रहा है। यमुना नदी ने पंजाब हरियाणा को पूरी तरह डुबो दिया है। और दूसरी गंगा से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, प्रयागराज बनारस गाजीपुर पटना बेगुसराय सीतामढ़ी दरभंगा जिले बुरी तरह प्रभावित है।इन शहरों कस्बों में मकान दो मीटर डूब गए हैं। हृष्ठक्रस्न, एसडीआरएफ

की टीम लोगो का घरों से बाहर निकाल रही है।

हिमालय और उत्तरी भारत में हुई भीषण बारिश का पानी अब मैदानों में पसर गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,में फसलों का कोई अतापता नहीं है।अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब हरियाणा,का दौरा किया।वे घोंटू घोंटू पानी में धान की फसल देखने गए।

भारत सरकार की एजेंसियां ने अनुमान लगाया है कि अकेले उत्तर प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

सबसे अधिक नुक्सान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हुआ है जहां पूरा बुनियादी ढांचा समाप्त हो गया है। कुल्लू मनाली में

चंडीगढ़ से आया हाइवे नष्ट हो गया है।वहां के मुख्यमंत्री श्री सुक्खू केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की गुहार लगा रहे हैं।

इस भीषण बारिश में न जाने कितने पुल ध्वस्त हो गए हैं। बिहार में भी गंगा नदी की बाढ में तबाही हुई है। दरअसल भारत में जनसंख्या के दबाव में विभिन्न कारणों से अनाप शनाप निर्माण कार्य हुए हैं जिसके चलते नदी नालों , नालियों पर अतिक्रमण हुए हैं।

इस वर्ष 1000 मिली मीटर से अधिक बारिश औसत हुई। इस कारण बाढ आना तय था। पूरे उत्तर भारत में बाजरा, धान, उड़द, ग्वार, मूंगफली,जैसी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है।

आधुनिक तकनीक एवं मानवीय करुणा है लोकतंत्र की बुनियाद

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

संयुक्त राष्ट्र ने 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में नामित किया है ताकि दुनिया भर में लोकतंत्र और उसके मूल सिद्धांतों का जश्न मनाया जा सके। विश्व समुदाय ने पहली बार 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाना नए या पुनर्स्थापित लोकतंत्रों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्वीकार किया, जिसने लोगों को दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने पर ज़ोर देने का अवसर प्रदान किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और दुनिया भर की सरकारों से नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने और लोकतंत्र में सार्थक एवं सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करना है। साथ ही, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का उद्देश्य 16 सतत विकास लक्ष्यों के साथ लोकतंत्र को संबोधित करना, सूचना तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करना, मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करना और प्रभावी, जवाबदेह, समावेशी संस्थाओं का विकास करना है। यह दिन दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र प्रेस और मौलिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं, जिन्हें सेंसरशिप और शारीरिक हिंसा के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है।

लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढाँचा है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा, कानून के शासन और निर्णय लेने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। 2024 में, दुनिया की लगभग आधी आबादी वाले 50 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, जिससे वैश्विक स्तर पर समाजों के भविष्य को आकार देने में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिवस भर नहीं है, बल्कि यह अवसर है कि हम यह परखें कि लोकतंत्र अपने आदर्श रूप में कितना जीवंत है और वास्तविक जीवन में कितनी चुनौतियों से जूझ रहा है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब लोकतंत्र ने अपनी जड़ों को मजबूत रखा, तब-तब समाज और राष्ट्र ने अभूतपूर्व प्रगति की, लेकिन जब-जब लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ हुआ, तब-तब अराजकता, अशांति, हिंसा, आतंक और तानाशाही प्रवृत्तियां हावी हो गईं। आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि लोकतांत्रिक देशों में ही लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

नेपाल में पिछले दिनों से चल रही अस्थिरता और आंदोलन यह दर्शाती है कि वहां की राजनीतिक नेतृत्व ने जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय सत्ता संघर्ष को वरीयता दी। बार-बार सरकार बदलना, नीतियों में असंगति, शासनगत भ्रष्टाचार और आमजन की समस्याओं की अनदेखी लोकतंत्र के मूल स्वरूप को ही चोट पहुँचाती है। यही हाल पाकिस्तान का है जहां लोकतांत्रिक ढांचा होते हुए भी सेना और सत्ता की सांठगांठ ने लोकतंत्र को खोखला बना दिया है। वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी और विपक्षी नेताओं पर दमन लोकतांत्रिक आदर्शों का उपहास है। बांग्लादेश में हाल के आंदोलनों ने यह स्पष्ट

कर दिया कि सत्ता का केंद्रीकरण लोकतंत्र का गला घोंटता है। वहां आम जनता और छात्रों की आवाज़ को कुचलने का प्रयास हुआ जिससे असंतोष उभरकर सामने आया। भूटान जैसे छोटे राष्ट्र में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपेक्षित रूप में मजबूत नहीं हो पा रही और सत्ता पर कुछ वर्गों का वर्चस्व देखा जा रहा है। ये उदाहरण बताते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने या संसद चलाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है नागरिक अधिकारों की रक्षा, समान अवसर, पारदर्शी शासन और जनता के प्रति जवाबदेही। जब नेता जनता से कट जाते हैं, जब संस्थाएं निष्पक्ष न रहकर सत्तापक्ष की कठपुतली बन जाती हैं, जब अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया जाता है, तब लोकतंत्र अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। यही वजह है कि आज लोकतंत्र विश्वव्यापी संकट से गुजर रहा है।

आज दुनियाभर की शासन-प्रणालियों में घर कर रही समस्याओं के समाधान का रास्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में है। सबसे पहले राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र अपनाना होगा, क्योंकि यदि दलों में ही तानाशाही हो तो राष्ट्र में लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? दूसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और मजबूत निर्वाचन प्रणाली लोकतंत्र की रीढ़ हैं, इन्हें किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देना चाहिए। तीसरा, नागरिक समाज और युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग और सक्रिय रहना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, 'लोकतंत्र जनता की आज्ञाकारिता नहीं, जनता की जागरूकता पर टिका है।' निश्चित है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, परंतु यह तभी प्रभावी हो सकता है जब इसके मूल तत्व-पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता और स्वतंत्रता को व्यवहार में उतारा जाए। यदि लोकतंत्र सही ढंग से चले तो इससे उन्नत शासन प्रणाली नहीं हो सकती। लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सतत साधना है, और उसकी रक्षा का दायित्व शासकों से कहीं अधिक जनता पर है। लोकतंत्र केवल एक शासन-प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन-मूल्यों और मानवीय गरिमा का उत्सव है। इसमें शासक और शासित का भेद मिट जाता है और सत्ता का वास्तविक केन्द्र जनता होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आत्मा में निहित है-जनता की सक्रिय भागीदारी और संवाद। जहाँ जनता मौन रहती है और केवल शासकों पर सब कुछ छोड़ देती है, वहाँ लोकतंत्र धीरे-धीरे खोखला हो जाता है और तानाशाही का रूप धारण कर लेता है। लोकतंत्र की सफलता का मूलमंत्र है-उत्तरदायित्व और पारदर्शिता। यदि सत्ता में बैठे लोग अपने को जनता से ऊपर समझने लगें, भ्रष्टाचार और पक्षपात में डूब जाएँ, तो लोकतंत्र के मूल तत्व ही नष्ट हो जाते हैं।

आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती है-मूल्यों का ह्रास। केवल बाहरी ढाँचे और प्रक्रियाएँ ही लोकतंत्र को जीवित नहीं रख सकतीं। जब तक नागरिकों में नैतिक चेतना, कर्तव्य-बोध और सामाजिक सरोकार नहीं होंगे, तब तक लोकतंत्र केवल बहुमत की तानाशाही बनकर रह जाएगा। जैसा कि प्रायः कहा गया है-'लोकतंत्र वही है जहाँ जनमत की गरिमा सुरक्षित हो, जनता की आवाज़ सुनी जाए और शासन जनता के कल्याण के लिए कार्य करे।' लोकतंत्र का दूसरा पहलू है-विकेन्द्रित शक्ति। यदि सारे निर्णय केवल शीर्ष पर सीमित रहेंगे और गाँव, नगर, पंचायत या स्थानीय निकाय निष्क्रिय रहेंगे तो लोकतंत्र अधूरा रहेगा। असली लोकतंत्र वही है जहाँ निर्णय जनता की ज़मीनी ज़रूरतों के अनुसार हों और सत्ता की प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर बहे। यह संवाद और सहमति का मार्ग है, संघर्ष और हिंसा का नहीं। इसे केवल व्यवस्था मानना भूल है; यह तो एक संस्कार और संस्कृति है, जो सतत् आत्मावलोकन, आत्म-सुधार और समावेशिता की माँग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हुए इसका सार यही है कि लोकतंत्र को बचाए रखने और उसे प्रभावी बनाने के लिए केवल संविधान और चुनाव काफी नहीं हैं; उसकी आत्मा को जीवित रखना आवश्यक है, जो जन-जागरण, नैतिकता और उत्तरदायित्व से ही संभव है। इस वर्ष लोकतंत्र दिवस मनाते हुए 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और लोकतंत्र' के विषयों पर ज़ोर दिया जा सकता है, जिसके तहत एआई के जिम्मेदार उपयोग से लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत करने की बात कही जाती है। यह दिन सभी के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और अधिक जीवंत डिजिटल भविष्य बनाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों, भागीदारी, और मानवाधिकारों पर सामूहिक रूप से काम करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक के इस युग में लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम तकनीक को केवल सुविधा का साधन न मानकर पारदर्शिता, संवाद और मानवीय मूल्यों को सशक्त करने का माध्यम बनाएँ। एआई लोकतंत्र को अधिक सहभागी और जवाबदेह बना सकता है-निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को डेटा-संपन्न, सटीक और पारदर्शी बनाकर, जनता की आवाज़ को त्वरित रूप से शासन तक पहुँचाकर। लेकिन यदि तकनीक केवल सत्ता या कॉर्पोरेट के हाथों का खिलौना बन जाए तो यह लोकतंत्र की आत्मा को कुचल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि तकनीकी नवाचार को मानवीय विवेक और करुणा से जोड़ा जाए। बढ़ती हिंसा, युद्ध और आतंक की स्थितियों का समाधान भी इसी में है कि हम संवाद, सहअस्तित्व और सहयोग को प्राथमिकता दें। लोकतंत्र को केवल राजनीतिक प्रणाली नहीं, बल्कि शांति और मानवीय गरिमा की संस्कृति बनाना होगा, जहाँ तकनीक मानवता की सेवा करे, विभाजन और विनाश का हथियार न बने।

यह निजी विचार है।

करोड़ों दिलों में राज करती हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं।

संजीव ठाकुर

हिंदी करोड़ दिलों में बसी हुई भाषा है। इसके अलावा विदेशों में भी करोड़ों लोगों के मध्य संवाद की भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है किंतु आज पर्यंत तक हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का सर्वोच्च सम्मान अभी भी अपेक्षित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी है ÷राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है÷ हिंदी की सार्वभौमिक स्वीकार्यता के कारण ही भारतीय राजनेताओं ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि हिंदी भाषा विदेशों में जितनी फ्ल फूल रही है बल्कि हिंदी बोलने वाले भारतवंशी कई देशों के राष्ट्र प्रमुख भी हैं और थे, जैसे ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ रामगुलाम, पुर्तगाल के एंटोनियो कोष्टा प्रधानमंत्री, श्री इरफान गुयाना के राष्ट्रपति, सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और सेसिल के राष्ट्रपति रामखेलावन पदस्थ हैं। इन देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हिंदी के विस्तार का बड़ा माध्यम बना हुआ है। हिंदी मूलतः बड़ी विशाल एवं आसानी से बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा है। भारत की भौगोलिक विशालता और विविधता के बावजूद हिंदी सर्व स्वीकार्य और देश की सर्व सम्मत भाषा है। यह अलग बात है कि अभी तक संवैधानिक रूप से इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आंदोलनकारियों ने यह महसूस किया की एकमात्र हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है जो दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश की संपर्क भाषा है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पर हिंदी भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो भारत में विभिन्न भाषा भाषाई नागरिकों के मध्य विचार विनिमय और संपर्क के लिए एक बड़ा सहारा है।

हिंदी के विशाल स्वरूप को मद्दे नजर रख पूर्व राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा ÷हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का या भाषा का बहिष्कार नहीं किया÷ यह शब्द हिंदी की पवित्रता और व्यापकता को इंगित करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों एवं समय काल मैं पूरे विश्व में 45 करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसकी सरलता एवं सहजता विश्व के लोगों को अत्यंत प्रभावित भी करती है। हिंदी के विद्वानों,शिक्षाविदों, लेखकों, रचनाकारों और युवा लेखकों द्वारा हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई है। कई नामचीन विद्वान लेखक जिन्होंने हिंदी को वैश्विक भाषाई शिखर पर पहुंचाया है। इसी अनुक्रम में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमतेन हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था। और हिंदी दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य राजकीय कार्यालयों इसके व्यापक प्रचार प्रसार एवं पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की ही है। हिंदी भाषा को पूरे विश्व में द्वितीय भाषा के रूप में माना जाता है। हिंदी नए वैश्विक स्तर पर अपने चलन के कारण अंग्रेजी भाषा को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। आज हिंदी भाषा का कंप्यूटर,इंटरनेट ई बुक, सोशल मीडिया, विज्ञापन, टेलीविजन रेडियो आदि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। भारत की विशाल जनसंख्या विदेशी व्यापारियों के लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां अपने सभी विज्ञापनों एवं सामानों में हिंदी भाषा का उपयोग कर भारतीय जनमानस को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करना चाहती है।यही वजह है कि हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार भी इसी माध्यम से हो रहा है। विदेशों में भारतीय फिल्मों ने भी हिंदी का बड़ा और वृहद प्रचार प्रसार किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, रूस मैं निवासरत भारतीय लोग हिंदी के प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं। वहां हिंदी बोली तथा समझी जाती है।

एनी बेसेंट ने सत्य कहा है कि भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में जो भाषा सबसे प्रभावशाली बन कर सामने आती है वह है हिंदी, जो हिंदी जानता है पूरे भारत की यात्रा कर हिंदी बोलने वाला से हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी अपने सामानों को बेचने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है। भारत में कुछ काले अंग्रेज लोग जो सिर्फमहानगरों में अंग्रेजी को ही महत्त्व देते हैं, उन्हें इस बात को समझ जाना चाहिए की भविष्य में हिंदी का भविष्य वैश्विक स्तर पर उज्जवल है। और उन्हें हिंदी भाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए।

वंशवाद में सिमटती देश की राजनीति

संजय सक्सेना,लखनऊ

भारतीय राजनीति में वंशवाद का मुद्दा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एलईडब्लूय) द्वारा 12 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट ने इस पुरानी समस्या को एक बार फिर ताज़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट में देशभर के 5,204 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की गहन पड़ताल की गई और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि हर पांच में से एक नेता, यानी लगभग 21 प्रतिशत जनप्रतिनिधि, राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की कमजोर होती नींव का प्रतीक है। लोकसभा में यह आंकड़ा और भी अधिक, 31 प्रतिशत तक पहुँच गया है। राज्यसभा में 21 प्रतिशत, राज्य विधानसभाओं में 20 प्रतिशत और विधान परिषदों में 22 प्रतिशत नेता परिवारवाद की छाया में राजनीति कर रहे हैं।परिवारवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उन युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है जिनके परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार, राष्ट्रीय जनता दल में लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव,समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव, तमिलनाडु में करुणानिधि की वंशवाद वाली सियासत, महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे,रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को,पंजाब में बादल परिवार,हरियाणा में चौटाला परिवार तो बसपा में मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश, पश्मिच बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही उत्तराधिकारी की कुर्सी क्यों मिलती है। क्या पार्टी में परिवार से बाहर के नेताओं की कमी रहती है।

बात राष्ट्रीय दलों से शुरू की जाये तो इसमें कांग्रेस सबसे आगे है। नेहरू-गांधी परिवार की विरासत यहाँ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे नाम सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में वंशवाद का प्रतीक बन चुके हैं। कांग्रेस के कुल नेताओं में 32 प्रतिशत परिवारवादी हैं। समाजवादी पार्टी (सपा) में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत, भाजपा में 17 प्रतिशत और वामपंथी दल सीपीआई(एम) में केवल 8 प्रतिशत है। इसके विपरीत, तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके जैसी दलों में यह प्रतिशत काफी कम है दृ 10 और 4 प्रतिशत। इसका कारण है कि ये दल मजबूत संगठन और काडर-आधारित संरचना पर विश्वास करते हैं, जिससे नए नेताओं को मौका मिल पाता है।

क्षेत्रीय दलों की स्थिति और भी चिंताजनक है। एनसीपी (शरद पवार गुट) और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 42-42 प्रतिशत नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। वाईएसआर कांग्रेस में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में 36 प्रतिशत है। यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत में भी परिवारवाद अब राजनीति का स्थायी हिस्सा बन चुका है। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसी के जगन मोहन रेड्डी इसके जीते-जागते उदाहरण हैं।

राज्यवार आंकड़े भी चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश वंशवाद का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। 604 जनप्रतिनिधियों में 141 (23 प्रतिशत) परिवारवादी हैं। लोकसभा में यूपी के 28 सांसदों में राहुल गांधी (रायबरेली), अखिलेश यादव (कन्नौज), अनुप्रिया पटेल (अपना दल), जितिन प्रसाद (पीलीभीत) और जयंत चौधरी (रालोद) शामिल हैं। राज्यसभा में रामगोपाल यादव, आरपीएन सिंह और नीरज शेखर जैसे नामों ने यह साबित किया कि यहां वंशवाद गहराई तक फैला हुआ है। समाजवादी पार्टी के 161 नेताओं में 48 (30 प्रतिशत) और भाजपा के 17 प्रतिशत नेता वंशवादी हैं।

अनुपात में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां 255 नेताओं में 86 (34 प्रतिशत) परिवारवादी हैं। महाराष्ट्र में 403 में 129 (32 प्रतिशत), बिहार में 360 में 96 (27 प्रतिशत), कर्नाटक में 326 में 94 (29 प्रतिशत) और असम में केवल 13 (9 प्रतिशत) नेता परिवारवादी हैं। तमिलनाडु (15 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (9 प्रतिशत) में काडर-आधारित दलों की मजबूती के कारण यह आंकड़ा कम है। झारखंड और हिमाचल प्रदेश में यह क्रमशः 28 और 27 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से यह साफ़होता है कि बड़े और प्रभावशाली राज्यों में वंशवाद लोकतंत्र को निगलता जा रहा है।

महिलाओं के मामले में स्थिति और भी गंभीर है। कुल 539 महिला सांसदों-विधायकों में 47 प्रतिशत (251) नेता सियासी परिवारों से हैं, जबकि पुरुष नेताओं में यह आंकड़ा केवल 18 प्रतिशत (856/4,665) है। उत्तर प्रदेश में 69 महिला नेताओं में से 29 (42 प्रतिशत), महाराष्ट्र में 39 में 27 (69 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश में 29 में 20 (69 प्रतिशत) और बिहार में 44 में 25 (57 प्रतिशत) महिला नेता परिवारवाद से आते हैं। तेलंगाना में यह आंकड़ा 64 प्रतिशत और गोवा-पुडुच्चेरी में 100 प्रतिशत है। भाजपा में 41 प्रतिशत और कांग्रेस में 53 प्रतिशत महिला नेता परिवार से हैं। सपा में यह संख्या 67 प्रतिशत है। इसका मतलब यह साफ़ है कि महिलाओं को राजनीति में लाने का मार्ग परिवारवाद के माध्यम से ही संभव होता है, जबकि गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के लिए अवसर सीमित रह जाते हैं।

वंशवाद केवल बड़े दलों तक सीमित नहीं है। छोटे और अपंजीकृत दलों के 87 नेताओं में से 21 (24 प्रतिशत) वंशवादी हैं। नौ दल पूरी तरह से परिवार आधारित हैं। निर्दलीयों में 94 में से 23 (24 प्रतिशत) नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं। यह दिखाता है कि वंशवाद हर स्तर पर गहरा चुका है और इसका दायरा न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों तक, बल्कि स्थानीय राजनीति तक फैल चुका है।

एडीआर की रिपोर्ट ने इसके चार प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है चुनावों का महंगा होना। एक औसत उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में दल उन लोगों को टिकट देते हैं, जिनके पास पैसा और नेटवर्क हो। दूसरा कारण है दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी नहीं होता और परिवार हावी हो जाते हैं। तीसरा कारण 'जीतने की क्षमता' का तर्क है। राजनीतिक परिवारों के नाम और नेटवर्क वोट दिलाने में मदद करते हैं। चौथा कारण सामाजिक न्याय के नाम पर बने दलों में भी परिवारवाद का प्रभाव है। सपा, आरजेडी जैसे दलों में परिवार ही राजनीति का केंद्र बन चुके हैं।

इस रिपोर्ट में वंशवाद को रोकने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी दिए गए हैं। सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि दलों में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सके। आंतरिक चुनाव और गुप्त मतदान के माध्यम से पद चयन और टिकट वितरण में पारदर्शिता लानी चाहिए। महिलाओं के लिए एक-तिहाई टिकट अनिवार्य की जानी चाहिए और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो। महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होगा और प्रॉक्सी या टोकन उम्मीदवारों की नीति समाप्त करनी होगी। उम्मीदवारों को परिवार की शक्ति के बजाय योग्यता के आधार पर चयनित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दलों को अपने चयन मानदंड सार्वजनिक करने होंगे और दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। चुनाव खर्च पर सख्त सीमा लगाई जानी चाहिए। युवाओं को भी मौके मिलें, गैर-वंशवादी उम्मीदवारों और महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाए और मतदाताओं को वंशवाद के नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए।

वंशवाद लोकतंत्र को धीरे-धीरे खोखला कर रहा है। यह नई प्रतिभाओं को दबाता है, जवाबदेही को कमजोर करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करता है। एडीआर की यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सभी दल कांग्रेस, भाजपा, सपा, टीडीपी को अपनी कमियों को सुधारना होगा। नेपाल में जेन जेड ने नेपोटिज़्म के खिलाफ आंदोलन कर सरकार तक गिरा दी। भारत के युवा भी अगर जागरूक हों, तो बदलाव की राह बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गैर-राजनीतिक युवाओं को मौका देने की बात कही है, लेकिन जमीनी बदलाव अभी धीमा है। सवाल यह है कि क्या हम योग्यता पर आधारित लोकतंत्र चाहते हैं या वंशवाद के खेल को जारी रखना चाहते हैं? जवाब आने वाला समय ही देगा।

यह निजी विचार है।

सांसद संतोष पांडे ने बजरंगपुर-नवागांव प्रकरण में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी

राजनांदगांव। सांसद माननीय श्री संतोष पांडे जी ने आज नगर पालिक निगम राजनांदगांव के बजरंगपुर-नवागांव प्रकरण में पीड़ित परिवारों से बजरंगपुर-नवागांव वार्ड में पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने ने कहा कि राजनांदगांव की शांति और सौहार्द्र के लिए प्रदेश में एक अलग पहचान है और इसे संस्कारधानी भी कहते है। विगत दिनों बजरंगपुर-नवागांव वार्ड में घटित हिंसा एवं हत्याकांड एक दुखद घटना है। नशे की गिरफ्त में आकर बिना किसी कारण के चाकूबाजी की घटना हुई और एक परिवार को बचाते हुए राजेश ढीमर की मृत्यु हो गई। चाकूबाजी की अन्य दूसरी घटना में सचिन दास मानिकपुरी एवं किशन राजपूत की हत्या की गई। पुलिस की शुरूआती कार्रवाई में पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तोड़-फोड़ की घटना की सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती तो यह घटना इस प्रकार का स्वरूप नहीं लेती। इस घटना के लिए थाना प्रभारी का दोष दिखाई देता है और उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में शामिल होने वाले अन्य लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

इस दौरान महापौर मधुसूदन यादव, पारस वर्मा,सावन वर्मा, आलोक श्रुति, सुमित भाटिया, किशुन यदु, चंद्रभान जांघेल, विनोद भारती, राहुल चौबे व अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह के अवसर बटमूल कॉलेज महापल्ली में विविध कार्यक्रमों का आयोजन

रायपुर।

रायगढ़- छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती समारोह को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य की 25 वर्षों की उपलब्धियों को जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति को आम जनता तक पहुँचाने के लिए वार्ड, ग्राम, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी परिपेक्ष्य में बटमूल आश्रम महाविद्यालय साल्हेओना महापल्ली जिला रायगढ़ के प्राचार्य डॉ पी एल पटेल के मार्गदर्शन एवं रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ के के गुप्ता नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने छत्तीसगढ़ के विकास एवं उपलब्धि से रिलेटेड रंगोली, चित्रकला, क्विज, भाषण प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन तथा रैली निकाल कर स्लोगन एवं नारों के माध्यम से लोगों को छत्तीसगढ़ के विकास एवं उपलब्धियों पर ध्यान आकर्षित किया। इस अवसर पर अतिथियों, गणमान्य नागरिकों के साथ महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष एनआर प्रधान, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पी एल पटेल, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो पी के कापड़ी, प्रो पी के गुप्ता, डॉ विक्रांत गुप्ता, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. के के गुप्ता, डॉ गीता देवांगन, प्रो नीलकंठ निषाद, प्रो प्रज्ञा विश्वाल, प्रो स्मिता पण्डा, प्रो लक्ष्मिन खड़िया, प्रो सुधा पटेल, त्रिलोचन बरेठ, यमुना मेहर, सुमन किसान, सुशिला यादव एवं महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आंध प्रदेश के तिरुमाला स्थित वेंगाम्बा अन्नप्रसादम परिसर में श्रद्धालुओं को प्रसाद परोसती हुईं।

नई दिल्ली में बम की धमकी के बाद कई बेंचों के अचानक उठ जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय के बाहर खड़ी एक एम्बुलेंस।

जीएसटी सुधार से जुड़ी उम्मीदों और दूसरी छमाही में बेहतर आय से निफ्टी में इस सप्ताह 1.32 प्रतिशत की तेजी दर्ज

मुंबई एजेंसी ।

वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में बेहतर आय और जीएसटी को तर्कसंगत बनाने और मौद्रिक नरमी के लाभों से प्रेरित वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में बेहतर आय की उम्मीदों के चलते इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखी गई। ऑटो और आईटी शेयरों में तेजी के चलते बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स क्रमशः लगभग 1.32 प्रतिशत और 1.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों, इंफोसिस की बायबैक घोषणा और टेक्नोलॉजी खर्च में सुधार को लेकर आशावाद के चलते आईटी सूचकांक में तेजी देखी गई।

निफ्टी 373 अंक बढ़कर एक बुलिश कैंडल बना रहा है। विश्लेषकों ने कहा कि वीकली चार्ट पर सूचकांक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ दिया है, जो आगे और तेजी की संभावना का संकेत देता है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के अनुसार, निफ्टी ने 25,100 के स्तर से ऊपर बने रहकर 25,114 पर बंद होकर मजबूती का प्रदर्शन किया। यह अपने प्रमुख ईएमए स्तरों से ऊपर कारोबार करना जारी रखे हुए है, जो तेजी के रुझान को दर्शाता है।

बेटियाँ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की पहचान हैं- सिंधिया

नईदिल्ली,एजेंसी

केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शनिवार को मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना के विस्तार की घोषणा और प्रधान डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (क्क्क्क्य) का शिलान्यास किया। केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि बेटियां हमारे समाज को गढ़ने का कार्य करती हैं और सुकन्या समृद्धि योजना केवल बैंक खाता नहीं, बल्कि यह माता का आत्मविश्वास, पिता का गर्व और पूरे समाज का भरोसा है। साथ ही उन्होंने बताया कि नवलोकार्पित पासपोर्ट सेवा केन्द्र से क्षेत्र के युवाओं और सभी नागरिकों को सुविधा और सहूलियत मिलेगी।

बेटियों के भविष्य पर भरोसे को मजबूत करने का आह्वान - केन्द्रीय मंत्री

सिंधिया ने मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना का विस्तार किया और बताया कि अन्य जिलों की तरह अब मुरैना की बेटियां भी अपने सपनों की उड़ान भरेंगी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मुरैना में सुकन्या समृद्धि योजना का विस्तार विदित रहे कि अब तक अशोकनगर की 929, शिवपुरी की 818 और गुना की 733 बेटियाँ, यानी लगभग 2500 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। सिंधिया ने याद दिलाया कि पिछली बार उन्होंने स्वयं बेटियों के खाते खुलवाए थे और निजी सहयोग भी किया था। इस अवसर पर उन्होंने दोहराया कि 1 मई 2026 तक जो भी बेटियाँ इस योजना से जुड़ेंगी, उनके खातों में उनका व्यक्तिगत सहयोग रहेगा। इस सहयोग को सिंधिया ने केवल आर्थिक नहीं, बल्कि क्षेत्र की बेटियों के सपनों को उड़ान का उत्प्रेरक बताया।

इस अवसर पर सिंधिया ने बेटियों के माता पिता से कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलकर वे सिर्फ बैंक से नहीं जुड़े हैं बल्कि उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य पर भरोसा जताया है। केन्द्रीय मंत्री ने सभी माताओं एवं पिताओं से इस भरोसे को हर महीने की बचत और हर रोज़ के सहयोग से और मजबूत करने का आह्वान किया।

सुविधा और सशक्तिकरण का नया अध्याय है पासपोर्ट सेवा केंद्र

मुरैना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए सिंधिया ने कहा कि अब जिले के नागरिकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ग्वालियर, गुना या भोपाल नहीं जाना पड़ेगा। इस केंद्र से मुरैना और श्योपुर जिले के साथ-साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। यह केंद्र प्रतिदिन 40 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध कराएगा। मंत्री सिंधिया ने कहा कि यह भवन आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा और सशक्तिकरण का प्रतीक बनेगा।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मुरैना में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शिलान्यास

सुविधा, सशक्तिकरण और सहूलियत के संगम-पथ पर अग्रसर है देश प्रदेश

सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और देश सुविधा, सशक्तिकरण और सहूलियत के संगम-पथ पर अग्रसर है। उन्होंने सभी नागरिकों को पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना पर बधाई दी और अभिभावकों से सुकन्या समृद्धि योजना से अधिक से अधिक जुड़ने का आह्वान किया।

रबी फसल के लिए 16 दिवसीय अभियान 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा

पीआईबी

अभियान से पहले सोमवार 15 सितंबर से 16 सितंबर तक दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय रबी सम्मेलन की तैयारियां पूरी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर पहली बार रबी सम्मेलन दो दिन का, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी होंगे शामिल

सम्मेलन में अभियान से पूर्व विभिन्न विषयों पर राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ कृषि अधिकारी करेंगे विचार-मंथन

पीआईबी

'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के पहले चरण की अपार सफलता के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। पिछली बार खरीफ फसल के लिए अभियान शुरू हुआ था और अब रबी फसल को लेकर देशभर के कृषि वैज्ञानिक इस अभियान के जरिए गांव-गांव जाकर किसानों से मिलेंगे, आवश्यक जानकारी देंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'लैब टू लैंड' मंत्र को साकार करने में भूमिका निभाएंगे। अभियान की तैयारियों के क्रम में ही 15 सितंबर से नई दिल्ली में दो दिवसीय 'राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025' पूसा, नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है।

रबी फसलों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन देशभर के कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति-निर्धारकों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ रबी 2025-26 की बुवाई सीज़न से संबंधित तैयारियों, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहन चर्चा होगी। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस अवसर पर अनेक राज्यों के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव, आईसीएआर के महानिदेशक सहित अन्य संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह के निर्देश पर पहली बार रबी सम्मेलन दो दिन का हो रहा है जिसमें कृषि से संबंधित चुनौतियां तथा रबी मौसम की फसलों के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा की जाएगी।

पहले दिन केंद्र एवं राज्यों के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। 16 सितंबर को सभी राज्यों के कृषि मंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री व राज्य मंत्री विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें नवीनतम तकनीक एवं बीजों को किसानों तक किस तरह प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए, इसके लिए गहन चिंतन एवं समीक्षा की जाएगी। सभी राज्यों के पदाधिकारी अपनी टीम के साथ इसमें भाग लेंगे , पहली बार इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया गया है, जो क्षेत्रीय अनुभव एवं चुनौतियां को साझा करेंगे तथा आगे की रणनीति तय करेंगे।

कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर समानांतर तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इनमें विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी तथा खुली चर्चा के माध्यम से व्यवहारिक समाधान सामने लाए जाएंगे। विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा ङ्क

जलवायु सहनशीलता, मृदा स्वास्थ्य एवं संतुलित उर्वरक उपयोग ङ्क बेहतर मृदा प्रबंधन और संतुलित पोषण पर बल।

गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं कृषि ट्रेसेबिलिटी ङ्क सटीक कृषि इनपुट और डिजिटल निगरानी। बागवानी का विविधीकरण ङ्क आय संवर्धन और निर्यात क्षमता पर केंद्रित रणनीतियाँ।

प्रभावी प्रसार सेवाएँ एवं कृषि विज्ञान केंद्रों (चङ्क्यह्य) की भूमिका ङ्क किसानों तक नवीनतम तकनीक एवं ज्ञान पहुँचाना।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का समन्वय ङ्क योजनाओं का बेहतर तालमेल और राज्यों के अनुभव साझा करना।

प्राकृतिक खेती ङ्क कम लागत एवं पर्यावरण अनुकूल खेती पद्धतियाँ।

दलहन एवं तिलहन पर विशेष बल के साथ फसलों का विविधीकरण तथा रबी फसलों के दौरान दलहन एवं तिलहन क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि हेतु रणनीतियाँ ङ्क आत्मनिर्भरता एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ावा।

रबी फसलों के दौरान उर्वरक उपलब्धता की स्थिति ङ्क समय पर आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा। एकीकृत कृषि प्रणाली सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की सफलताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके। साथ ही, मौसम पूर्वानुमान, उर्वरक प्रबंधन, कृषि अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप से जुड़े विषयों पर भी विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

केरल 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला आयोजित करेगा

केरल सरकार की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती वीना जॉर्ज आयुष डिजिटल ढांचे को मजबूत करने संबंधी कार्यशाला का उद्घाटन करेंगी

पीआईबी

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन के विभागीय शिखर सम्मेलन 2025 में ÷विभिन्न क्षेत्रों में आईटी-सक्षम डिजिटल सेवाएं÷ को एक प्रमुख उप-विषय के रूप में पहचाना गया। इसके फॉलोअप में केरल के कोट्टायम में 18-19 सितंबर 2025 को ÷आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान÷ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

इस कार्यशाला को आयुष क्षेत्र में डिजिटल समाधानों को मज़बूत करने और एक संपूर्ण, केंद्रीकृत व इंटरऑपरेबल डिजिटल फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य मानकीकरण सुनिश्चित करना, दोहराव से बचना, मापनीयता को बढ़ावा देना, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देना और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सुधार करना है।

18 सितंबर को उद्घाटन सत्र की शुरुआत केरल सरकार के एनएएम के मिशन निदेशक डॉ. साजिथ बाबू के स्वागत भाषण से होगी।

केरल सरकार की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती वीना जॉर्ज उद्घाटन भाषण देंगी। इसके बाद केरल सरकार के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) श्री राजन खोबरागड़े अध्यक्षीय भाषण देंगे।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा मुख्य भाषण देंगे तथा आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती कविता जैन द्वारा विशेष संबोधन दिया जाएगा। इस कार्यशाला में आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रशासक, राज्य आयुष विभागों के मिशन निदेशक और प्रमुख अधिकारी, केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आयुष आईटी प्रभागों के तकनीकी कर्मचारी और डिजिटल स्वास्थ्य एवं ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों के विशेषज्ञ भाग लेंगे।

इस विचार-विमर्श में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने और आईटी नवाचारों को प्रदर्शित करने, आयुष ग्रिड टीम द्वारा केंद्र सरकार के आईटी समाधानों पर ओरिएंटेशन प्रदान करने और कार्यक्रम प्रबंधन, रोगी देखभाल, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली, मानव संसाधन एवं डेटा प्रबंधन, और वित्तीय ट्रैकिंग तंत्र जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल डोमेन को परखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यशाला से सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है। इसमें आईटी-सक्षम आयुष सेवाओं पर एक समेकित राष्ट्रीय ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म की स्थापना, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानकीकृत डिजिटल को अपनाने के लिए एक रूपरेखा का विकास, और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और अन्य राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य पहलों के साथ आयुष डिजिटल प्रणालियों को जोड़ने के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

दादा –दादी के सम्मान में जय भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल में उत्साह पूर्वक मनाया गया, ग्रैंडपेरेंट्स डे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से जताया प्रेम

लोकशक्ति संवाददाता

/जांजगीर चांपा / हरिराम गट्टानी मेमोरियल जय भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज दिनांक 13 सितंबर 25 दिन शनिवार को ग्रैंडपेरेंट्स -डे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया ।कार्यक्रम में बच्चों के दादा-दादी, नाना -नानी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यादायिनी माता सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। पधारे गए समस्त ग्रैंडपेरेंस का बड़े ही आदर व सम्मानित वातावरण में उत्साह पूर्वक छोटे-छोटे बच्चों द्वारा तिलक कर व बैच लगाकर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार गट्टानी, संचालक अजय कुमार गट्टानी,प्रबंधक हर्षित गट्टानी विद्यालय प्राचार्या श्रीमती गुरमीत कौर धनजल मैम,प्रबंध समिति के सदस्य श्रीमती गंगा गट्टानी ,श्रीमती सुनीता गट्टानी, हर्षवर्धन गट्टानी उपस्थित थे। छोटे-छोटे बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य तथा बुजुर्गों के सम्मान में प्रेरणादायक नाटक प्रस्तुत किया गया ।बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की गई। इस दौरान बुजुर्गों ने अपने जीवन अनुभव साझा किए और बच्चों को आशीर्वाद दिया। विद्यालय परिवार ने वरिष्ठ नागरिकों को समाज की धरोहर बताते हुए उनके योगदान का सम्मान किया। इस उत्सव में उनके सम्मान में उनकी भावनाओं से जुड़ी खेल जैसी गतिविधियां शामिल थीं। जिनमें दादा - दादी ने उत्साह पूर्वक भाग लिया ,खेल जीतने वाले ग्रैंडपेरेंट्स को उपहार से सम्मानित किया गया ।जिसमें अनन्या केशरवानी कक्षा- 2 के दादा जी श्री आर. के. केशरवानी ,दादी जी मनीषा केशरवानी , भव्या सिंह राजपूत कक्षा 1-ब के दादी जी गायत्री देवी राजपूत और दादा जी पारस कुमार विजेता रहे।जिससे उनके चेहरे पर खुशी स्पष्ट झलक रही थी। विद्यालय प्रबंधन ने ग्रैंडपेरेंट - डे को ज्ञान और भावनात्मक सहयोग को पहचानने का एक अवसर बताया, जो पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है ।विद्यालय प्राचार्या श्रीमती गुरमीत कौर धनजल मैम ने इस तरह से कार्यक्रम करने का उद्देश्य पारिवारिक बंधनों और परंपरा को मजबूत करना तथा सांस्कृतिक पहचान और पारिवारिक इतिहास को आकार देने में बड़ों की भूमिका को बताया यह कार्यक्रम विद्यालय प्राचार्य के मार्गदर्शन में बहुत ही उल्लास पूर्ण भावनात्मक संदेश देते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में सफल रूप से संचालित हुआ।

राजनांदगांव में तकनिकी संघ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मैं क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन*

डामन लाल साहू अध्यक्ष,श्याम लाल जैन महामंत्री बने राजनांदगांव। आज दिनांक 13सितंबर 2025 को प्रांतीय पदाधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी तकनीकी संघ द्वारा राजनांदगांव के संभागीय कार्यालय में कार्यकारिणी सदस्यों का गठन किया गया। जिसमें की संघ द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एवं सर्वसम्मति से अध्यक्षः- डॉमन लाल साहू उपाध्यक्षः- श्यामल जैन महामंत्रीः- टीकेंद्र साहू,सचिव :- संजय जार्घेल,मनोहर साहू, कोषाध्यक्षः नंदलाल पटेल, दिग्विजय,मीडिया प्रभारीः - मनु साहू, बृजेश देवांगन तकनीकी संघ का गठन किया गया।

नशा मुक्ति के खिलाफग्रामीणों ने की आवाज बुलंद गांव में लगा जगह-जगह पूर्ण शराब बंदी का संदेश

सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले को 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा

राजनांदगांव।जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम रेंगाकठेरा (डोगरगांव) एवं खुज्जी से लगे ग्राम बेंदरकट्टा मे भी बीते कुछ दिनों पूर्व पूर्ण शराबबंदी की गई है।

पूर्ण शराबबंदी गांव या बाहरी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक जगह शराब पीने पर ?10,000 का अर्थदंड व कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यह निर्णय आदेश अनुसार ग्राम विकास समिति एवं समस्त ग्रामवासी रेंगाकठेरा, बेंदर कट्टा मे हुआ है। ग्रामीणजनों ने जगह-जगह पर पूरे बस्ती में फ्लेक्स लगाकर लोगों से आह्वान किया है। ग्रामीण जनों ने बताया कि नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाकर गांव को पूर्ण शराबबंदी की गई है ग्रामीण जनों ने बताया कि गांव के छोटे-छोटे बच्चे एवं महिलाएं को शराबियों के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा एवं आर्थिक तंगी का सामना परिवार जनों को करना पड़ता था गांव का माहौल हर हमेशा खराब रहता था जिसकी वजह से ग्रामीण जनों ने ठोस निर्णय लेते हुए पूर्ण शराब बंदी का निर्णय लिया जिसका परिपालन ग्रामीण जन स्वतःही कर रहे हैं।

सर्व समाज के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की अनुकरणीय पहल

स्व. श्रीमती द्रोपती देवी अग्रवाल एवं स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल (पहरियां वाले) की स्मृति में 17 सितंबर को.....

होगा मेगा हेल्थ कैंप, कैंसर जागरुकता सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांच का मिलेगा लोगों को लाभ.....

जांजगीर चांपा

जिला मुख्यालय जांजगीर नैला में स्थापित श्रीमती द्रोपती देवी अग्रवाल केदारनाथ फाउंडेशन ने जहां अपने स्थापना के बाद से ही निरंतर सेवा एवं रचनात्मक कार्यों में एक अनुकरणीय पहल की है, तो वहीं इस फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जरूरतमंदों की सेवा के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, तथा इस फेडरेशन के द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्रियों का वितरण, सर्व समाज के लोगों को देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों की निशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधाओं का लाभ दिलाने की दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है, तो वहीं इस फेडरेशन के सदस्यों द्वारा भी पूरी सक्रियता के साथ फेडरेशन स्थापना की उद्देश्यों के अनुरुप कार्य किया जा रहा है, तथा श्रीमती द्रोपती देवी केदारनाथ अग्रवाल फाउंडेशन नैला जांजगीर के डायरेक्टर समाज सेवी संजय अग्रवाल जांजगीर, समाज सेवी अजय अग्रवाल प्रेसिडेंट एम बी पावर प्राइवेट लिमिटेड, समाजसेवी मनीष अग्रवाल ने बताया है कि आने वाले 17 सितंबर को नैला स्थित श्री अग्रसेन भवन निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कैंसर जागरुकता से संबंधित भी विशेष रूप से प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा जानकारी दी जाएगी, तथा इस फाउंडेशन द्वारा विगत वर्ष भी नवरात्रि पर्व से पूर्व जहां जांजगीर- नैला सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा के बड़े कार्य किए गए तो वहीं सफलतम निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी भव्य आयोजन कर सैकड़ो लोगों को चिकित्सा परामर्श सुविधा का लाभ दिया गया थाद्य इस वर्ष भी श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के पावन मौके पर श्री अग्रसेन भवन नैला में स्व. श्रीमती द्रौपदी बाई अग्रवाल एवं स्व. श्री केदारनाथ अग्रवाल जी (पहरिया वाले) की स्मृति में अपोलो हॉस्पिटल्स बिलासपुर एवं श्री अग्रसेन सेवा समिति नैला-जांजगीर के संयुक्त तत्वाधान में सर्व समाज हेतु विशाल स्वास्थ जागरुकता एवं निःशुल्क हैल्थ चैकअप कैंप का भव्य आयोजन किया गया है, उपरोक्त जानकारी देते हुए शिविर के प्रायोजक संजय केदार अग्रवाल एवं डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 17 सितंबर दिन-बुधवार को समयः सुबह 10:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक यह शिविर होगा, जिसमें कैंसर जागरुकता को लेकर स्पीकर : डॉ.

अमित वर्मा वरिष्ठ कैंसर सर्जन, अपोलो कैंसर सेंटर के विशेष मार्गदर्शन में अपोलो के ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ डॉ. रश्मि शर्मा (स्त्री रोग विशेषज्ञ), डॉ. आकाश गर्ग (उदर (पेट) रोगविशेषज्ञ), डॉ.एम.पी. सामल (हृदय रोग विशेषज्ञ), डॉ. मंदार गोकाते (जनरल फिजिशियन), डॉ. संकेत ठाकरे (स्पाइन सर्जरी एवं हड्डीरोग विभाग), डॉ. विक्रम साहू (स्पाइन सर्जरी एवं हड्डीरोग विभाग), डॉ. विक्रम साहू (ज्वाइंट रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट एवं विभागाध्यक्ष फिजियोथेरेपी विभाग) प्रमुख रुप से अपना चिकित्सापरामर्श देंगे इसके अलावा शिविर मेंनिःशुल्क जाँचः ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर जनरल वाइटल्स एवम टाइटन आई प्लस द्वारा निःशुल्क आँखों की जाँच की जाएगी,शिविर के प्रायोजक परिवार के सदस्यों ने बताया कि उपरोक्त शिविर का लाभ लेने हेतु अधिक जानकारी एवं पंजीयन हेतु संपर्क करें किशोर शर्मा-9713122819, शुभम तिवारी-9109754033, हिमांशु यादव-9303478658, आकाश सिंघानिया 7879963975, अनुभव अग्रवाल8085415395, अखिल बंसल-9827979541 से संपर्क कर अपना अग्रिम पंजीयन करवा सकते हैं।17 सितंबर को आयोजित शिविर के प्रायोजक - संजय केदार अग्रवाल, अजय अग्रवाल (प्रेसिडेंट एम.बी. पावर, अनूपपुर) है, तथा शिविर को सफल बनाने के लिए श्री अग्रसेन सेवा समिति नैला-जांजगीर एवं अपोलो हॉस्पिटल्स बिलासपुर अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं।

निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने स्पीच थेरेपी सेन्टर का अवलोकन किया।

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित वाणी वाचन, एवं श्रवण अनुसंधान एवं विशेष दिव्यांग बच्चों का स्कूल शिक्षा का मन्दिर का श्री लोकेश कावड़िया अध्यक्ष निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम ने अवलोकन किया। सप्रे शाला परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद का मुख्य कार्यालय के साथ पूरे परिसर में होने वाले स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी , बिहेवियर थेरेपी , श्रवण क्षमता की जांच करने वाली बेरा मशीन , आदि सभी का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के पश्चात श्री कावड़िया ने उपस्थित बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी ली और परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य को सराहा और भविष्य में उनके द्वारा यथा संभव सहयोग करने की बात कही। इस दौरान मेट्स विश्वविद्यालय में विदेशों से अध्ययन करने वाले छात्रों का भी एक दल स्पीच थेरेपी सेन्टर देखने पहुंचे थे और भविष्य में इस संस्थान में इंटरशिप करने की इच्छा व्यक्त किए । इस अवसर पर श्री लोकेश कावड़िया जी को शाल , श्रीफल , एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया । इस अवसर पर परिषद के महासचिव चंद्रेश शाह, कोषाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जैन, संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम कार्यकारिणी सदस्य छगनभाई पटेल और परिषद के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनचौपाल लगाकर पीएम आवास हितग्राहियों से किया जा रहा संवाद

चांपा।

आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने व गुणवत्ता के लिए जिला प्रशासन की पहल*

जांजगीर-चांपा / केंद्र एवं राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जांजगीर-चांपा जिले में निरंतर तेज गति से क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना में और ज्यादा प्रगति लाने के लिए कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में जिले में हितग्राहियों के बीच जनचौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों में जिला एवं जनपद पंचायत की तकनीकी सहायकों की टीम हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। जनचौपाल से आवास निर्माण में बेहद कारगर प्रगति देखने को मिल रही है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आवास पूर्ण करने के लिए ग्राम पंचायत में हितग्राहियों के बीच चौपाल लगाकर संवाद किया जा रहा है। तकनीकी टीम के द्वारा निर्माण कार्यों की सतत निगरानी भी हो पा रही है। स्वीकृत किए जा चुके आवासों में से लगातार परिवारों के पक्के आवास पूर्ण हो रहे है। प्रगतिरत आवासों को पूर्ण किया जाना शेष है। जनचौपाल में संवाद के चिन्हित ग्राम पंचायतों में तकनीकी सहायकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सलाह और संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जनचौपाल कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है। जनपद पंचायत पामगढ़ की ग्राम पंचायत डोंगाकोहरोद में जन चौपाल लगाकर ग्रामीण हितग्राहियों ने अपनी बात रखते हुए कई शंका समाधान किए। इसके साथ ही तकनीकी अमले ने भी अधूरे आवासों को पूर्ण करने के लिए ग्रामीणों का प्रेरित किया। जन चौपाल में सरपंच सचिव, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। पीएम आवास योजना की टीम द्वारा तकनीकी सलाह और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को भी प्रोत्साहित कर रही है। आपसी संवाद से हर समस्या का निराकरण करते हुए जांजगीर-चांपा जिले में लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत आवासों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है।

तुमड़ीबोड –कोहका क्षेत्र में अवैध शराब एवं सट्टा का कारोबार जोरों पर

नेशनल हाईवे के ढाबो में खुले आम बेची व पिलाई जा रही है शराब**

राजनांदगांव। जिले के तुमड़ी बोड - कोहका पुलिस चौकी तुमड़ीबोड अंतर्गत आने वाले ग्रामों में एवं नेशनल हाईवे स्थित ढाबों में खुलेआम अवैध शराब बेची जा रही व सट्टा का कारोबार जोरो से चल रहा है।अवैध शराब एवं सट्टा के कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए ग्रामीण जनों ने बताया कि तुमडीबोड पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में अवैध शराब बिक्री एवं सट्टा का कारोबार जोर-शोर से चल रहा है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नेशनल हाईवे की तुमडी बोड की यारा द ढाबा, सतविंदर ढाबा,बिहारी ढाबा, शेरे पंजाब ढाबा मलई डबरी, इंदामरा कोहका,पेटेश्री सहित अनेक जगह खुलेआम शराब बिक्री एवं पीने पिलाने का कार्य जोरो से चल रहा है।

अवैध शराब बिक्री के कारण बढ़ते युवाओं में नशा के प्रति आदत के कारण बीते दिनों में पेटे श्री ग्राम में महाकाल यात्रा के दौरान एक युवक की हत्या, नशे मे लत युवाओं के कारण हुई थी।

एक तरफ गांव-गांव में पूर्ण शराब बंदी की जा रही है जिसका अच्छा प्रतिफल अच्छा माहौल लोगों को देखने में मिल रहा है दूसरी तरफ खुले आम अवैध शराब बिक्री करके लोगों को मौत के मुंह की तरफले जा रहा है आज के छोटे-छोटे बच्चे नशे की लत की ओर बढ़ रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में ग्रामवासियों को जागरूक करने हेतु चर्चा की गई।जिससे नशा प्रवृत्ति के कारण घर परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है एवं गांव का माहौल खराब रहता है ग्रामीणों ने कहा कि इसकी सूचना संबंधित पुलिस चौकी तुमड़ीबोड थाना प्रभारी को कई बार दी जा चुकी है लेकिन आज तक अवैध शराब एवं सट्टा का कारोबार बंद नहीं हो पाया है ग्रामीणों ने शासन प्रशासन, एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि गांवो, ढाबो में अवैध शराब एवं सट्टा का कारोबार को बंद करने की मांग की है।

खेल हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाते हैं - उप मुख्यमंत्री श्री साव

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विद्या भारती मध्य क्षेत्रीय व्हालीवॉल एवं खो–खो खेलकूद प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं

जांजगीर-चांपा संवाददाता

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने आज चांपा के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विद्या भारती मध्य क्षेत्रीय व्हालीवॉल एवं खो-खो खेलकूद प्रतियोगिता शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री साव एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा भारत माता एवं सरस्वती माता के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने सभी विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों से कहा कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मैदान में पसीना बहाना चाहिए, क्योंकि यही पसीना जीवन की ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखता है। उन्होंने कहा कि जो छात्र-छात्राएँ प्रतियोगिताओं में भाग लेने आते हैं, वे अपनी रुचि और लगन से खेल के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। मन, समर्पण और संकल्प के साथ खेलने पर ही सफलता मिलती है। आज के आधुनिक भारत में हर खिलाड़ी का लक्ष्य होना चाहिए कि वह न केवल जीते, बल्कि अपने माता-पिता, समाज, राज्य और देश का नाम भी रोशन करे। खेल में हार का कोई अस्तित्व नहीं है या तो खिलाड़ी जीतता है या सीखता है। यह अनुभव जीवन भर काम आता है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि डिप्रेशन, निराशा, अवसाद और दुख को अपनी डिक्शनरी से निकाल फेंकना चाहिए। निराश और परेशान व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा होगा वही समाज में और जीवन में प्रगति करेगा। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएँ, प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

कार्यक्रम को श्री जुड़ावन सिंह ठाकुर, श्री विवेक सक्सेना, श्री चंद्रशेखर देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि खिलाड़ियों की सहभागिता और उनकी उपलब्धियाँ हम सबके लिए गर्व की बात हैं। उन्होंने कहा कि जीतना और हारना दोनों ही हमें जीवन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। खेल जीवन का अहम हिस्सा है इससे हम अपना समुचित विकास कर सकते हैं।

इस दौरान इस अवसर पर जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र सांसद श्रीमती कमलेश जांगडे, पूर्व संसदीय सचिव श्री अंबेश जांगड़े, श्री प्रदीप नामदेव नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार साहू, श्री गुलाब सिंह चंदेल, श्री अमर सुल्तानिया, इंजीनियर रवि पांडे, श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, श्री प्रशांत ठाकुर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

हायर सेकेंडरी करमरी स्कूल के 41 छात्राओं को मिली साइकिल

राजनांदगांव।छुरिया क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करमरी में सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत 41 नग साइकिल वितरण किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत करमरी सरपंच दीनदयाल साहू,शाला विकास समिति अध्यक्ष लक्ष्मण साहू संस्था के प्राचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं की उपस्थिति में वितरण की गई। मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत सरपंच दीनदयाल साहू ने सभी छात्राओ को बधाई एवं शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूलों में छात्रों को निःशुल्क साइकिल बांटने की योजना चलती है जिसके योजना अंतर्गत सरस्वती साइकिल योजना इन योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को स्कूल आने-जाने में मदद करना शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है योजना है छात्राओं को बिना किसी परेशानी की स्कूल पहुंचने में मदद करती है शिक्षा को बढ़ावा मिलती है इससे लड़कियों के स्कूल में नामांकन में वृद्धि होती है यह योजना सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस योजना के तहत नवमी कक्षा की छात्रों को साइकिल बाटी जाती है ताकि वे स्कूल आसानी से आ जा सके।

खास खबर

सेजस गोपालपुर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित

कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वर्ष (रजत जयंती वर्ष) पूर्ण होने के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार सेजस गोपालपुर में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसी क्रम में विगत दिवस सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री दिनेश कुमार भारद्वाज, सेवानिवृत्त व्याख्याता श्रीमती निर्मला पटेल, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक सिसिलिया लकड़ा विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्या डॉ श्रीमती सीमा भारद्वाज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि शिक्षक के रूप में शासन के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही हम सबको दिया गया है,जिसका निर्वहन हम सभी को सच्ची लगन से करना चाहिए। आज के विद्यार्थी कल के देश के भविष्य हैं,उनका भविष्य संवारने का दायित्व शिक्षकों का है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों को साल, श्रीफल, डायरी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह में सभी विशिष्ट अतिथियों के द्वारा अपने -अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए सच्चे सेवा भाव से विद्याध्ययन करने हेतु आवाहन किया गया।कार्यक्रम में विद्यालय के सभी व्याख्यता, शिक्षक,शिक्षिकाएं एवं स्टाफ उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री शैलेश उपाध्याय व्याख्याता के द्वारा एवं आभार प्रदर्शन वरिष्ठ व्याख्याता श्री विनोद कुमार साहू के द्वारा किया गया।

जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

कोरबा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के तत्वधान एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में वर्ष 2025 में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितंबर को आयोजित होगी। लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक मंच है जिसका उद्देश्य विवादों को आपसी समझौते से निपटाना है, बिना लंबी प्रक्रिया के। लोक अदालत मे राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान का निराकरण होगा, साथ ही ऐसे मामले जो न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण किया जायेगा जिसमें बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर बकाया, टेलीफोन बिल इत्यादि। जिला न्यायालय के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ जिला एवं सत्र न्यायालय कोरबा मे लगेगी साथ ही व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली में भी खण्डपीठ का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा द्वारा जनसामान्य से अपील की गई है कि नेशनल लोक अदालत में सक्रिय सहाभागिता लेकर उसका लाभ प्राप्त करें जिससे नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

वायुसेना से सौर सेना तक अजय राज बेन की उज्ज्वल कहानी सौर ऊर्जा से शून्य हुआ बिजली बिल,

बढ़ी बचत और जुड़ा पर्यावरण संरक्षण

संवाददाता

कोरबा हर घर रोशन हो, हर परिवार आत्मनिर्भर बने इसी सपने को साकार कर रही है भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना ने आज देश के करोड़ों परिवारों के जीवन में बदलाव ला रही है। यह केवल बिजली उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला, जो ऊर्जा नगरी के रूप में पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है, अब पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। यहाँ के ग्रामीण और शहरी परिवार इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भरता और बचत की नई मिसालें गढ़ रहे हैं। इन्हीं लाभार्थियों में दादरखुर्द निवासी श्री अजय राज बेन भी शामिल हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाकर अपने परिवार के जीवन में नया उजाला लाया।

भारतीय वायुसेना में सेवाएँ देने के बाद अब वह समाज में ऊर्जा सशक्तिकरण के प्रतीक बन चुके हैं। वर्ष 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से उन्हें 78,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिसने इस स्थापना को सहज और किफायती बना दिया। सौर ऊर्जा से अब उनके घर की हर ज़रूरत पूरी होती है। पंखे, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन और अन्य सभी घरेलू उपकरण अब बिना किसी रुकावट के चलते हैं। पहले जहाँ हर माह बिजली बिल की चिंता होती थी, वहीं अब उनके घर का बिल शून्य हो गया है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भी भेजी जाती है, जिससे न केवल राज्य के ऊर्जा संतुलन में उनका योगदान है, बल्कि यह ऊर्जा अन्य जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुँच रही है।

उन्हें इस योजना की जानकारी अखबार में प्रकाशित एक विज्ञापन से मिली। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोसी की मदद से आधिकारिक वेबसाइट ीजजचरूध्ध्चउेनतलंहींतण्हवअण्पद पर आवेदन किया। आवेदन प्रक्रिया सरल और पूरी तरह पारदर्शी रही। आवेदन के बाद विशेषज्ञ टीम ने उनके घर का सर्वेक्षण किया और निर्धारित समय-सीमा में सोलर पैनल की स्थापना कर दी। पूरी प्रक्रिया में न तो किसी प्रकार की जटिलता रही और न ही किसी तरह की बाधा। उन्होंने बताया कि सरकार ने जिस पारदर्शी व्यवस्था और समयबद्धता के साथ इस योजना को लागू किया है, वह सचमुच सराहनीय है। श्री बेन का कहना है कि इस योजना ने उन्हें दोहरा लाभ मिला है। एक ओर उनके परिवार को मुफ्त और अबाधित बिजली मिल रही है, वहीं दूसरी ओर वे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। कोयला और डीजल जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहने की बजाय वे अब सूर्य की असीम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आज दादरखुर्द ही नहीं, बल्कि आसपास के गाँवों और इलाकों में भी कई लोग उनकी सफलता से प्रेरित होकर इस योजना से जुड़ रहे हैं। उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र इस पहल को देखकर उत्साहित हैं और सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केवल आज की ऊर्जा आवश्यकताओं का समाधान नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य का आधार है। इस योजना से हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर भारत तेजी से आत्मनिर्भर ऊर्जा राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। कोरबा जैसे औद्योगिक जिले में जहाँ कोयला उत्पादन की पहचान रही है, वहां यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सरकार की योजनाएँ न केवल लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं, बल्कि हरित विकास और सतत भविष्य की नींव भी रख रही हैं। अपने अनुभव साझा करते हुए श्री अजय राज बेन कहते हैं ÷अब मुझे यह चिंता नहीं रहती कि बिजली का बिल कितना आएगा। सूर्यघर योजना ने सचमुच घर-घर में रोशनी और उम्मीद जगाई है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हम जैसे आम नागरिकों के जीवन में इतनी बड़ी सुविधा और आत्मनिर्भरता का मार्ग खोला। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना वास्तव में एक ऐतिहासिक कदम है।÷ यह योजना वास्तव में भारत सरकार की उस दूरदृष्टि को दर्शाती है, जिसमें हर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाकर देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का सपना साकार हो रहा है।

स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एन केशरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

कोरबा,। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस एन केशरी की अध्यक्षता में खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया गया जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। इस समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने की योजना बनाई गई और अन्य सभी विभागों से को-ऑर्डिनेट कर कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा भी तय की गई। इस समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की शत प्रतिशत आधार आधारित उपस्थिती,नेक्स्ट जेन,आरबीएसके,आयुष्मान भारत,वय वंदन, आभा आईडी, टीवी, कुष्ठ, मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, टीकाकरण, आरोग्य मेला, आईडीएसपी, एनआरसी, एनसीडी,परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव और मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु के संबंध में विस्तृत समीक्षा कर कमियों में सुधार के आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शत-शत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आधार आधारित उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है.सभी चिकित्सालय में नेक्स्ट जैन के समस्त मॉड्यूल पर कार्य करना है, टीवी कार्यक्रम की समीक्षा के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में टीबी के केस ज्यादा है उन क्षेत्रों में कैंप मोड में टीवी केस के प्राइमरी कांटेक्ट,फैमिली मेंबर सहित आसपास के 50 घरों में टीवी जांच तथा एक्सरे किया जाना है।तथा सभी परिवार के सदस्यों को निक्षय पोर्टल में एंट्री किया जाना है उनका सी वाय टेस्ट करना है दूसरे भाग में जिन क्षेत्रों में केस नहीं है वहां कार्य करना है टीवी शंका स्पद मरीजों की अधिक से अधिक संख्या में जांच करना है जहां टीबी के मरीज ज्यादा है वहां सभी बच्चों को 15 दिन के भीतर जांच किया जाए।

कुष्ठ की संभावित मरीजों की जांच छेत्र के पीएचसी में कराया जाए।सिकल सेल की जांच 40 वर्ष तक के सभी लोगों का सॉल्युबिलिटी टेस्ट करना है हाइड्रोक्सी यूरिया सभी मरीजों को देना है साथ ही सभी को पोर्टल में एंट्री करें। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की समीक्षा के तहत सभी लोगों का आभा आईडी जारी करना है उन्होंने नियमित आरोग्य मेला लगाने के निर्देश दिए तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उन्होंने निर्देशित किया कि सी एच ओ मानसिक रोगियों की स्क्रीनिंग कर मेंटल हेल्थ विभाग में डॉक्टर से टेलिस मानस कंसल्टेशन कराएंगे।टीकाकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि सभी डिलीवरी प्वाइंट में होने वाले प्रसव की एंट्री यू वीन पोर्टल में तथा टीकाकरण सत्रों में लगाए जा रहे वैक्सीन को भी युविन पोर्टल में एंट्री करना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त उन्होंने मौसमी बीमारी दावाओं की उपलब्धता,मांग पत्र भेजने, संस्थागत प्रसव बढ़ाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम में पीपीआईयूसीडी केस बढ़ाने,समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की उपलब्धि शत प्रतिशत प्राप्त करने तथा किसी भी ग्राम में आउटब्रेक होने की सूचना देने, आवश्यक कार्यवाही करने सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।

युवक से मारपीट कर मोबाईल लूटने वाले आरोपी पकड़ाये

मुंगेली, मुंगेली जिले की चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी पुलिस ने एक युवक के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर उसका मोबाईल फोन लूटने वाले आरापियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 296,115(2),351(2),3(5) बीएनएस के तहत कार्यवाही की गई है साथ ही विवेचना के दौरान धारा 309 बीएनएस भी जोड़ी गयी है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 29.08.2025 को प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू पिता रामकुमार साहू उम्र 23 वर्ष निवासी साल्हेघोरी चौकी डिण्डौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली का चौकी डिण्डौरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.08.2025 को अपने निजि काम से खाम्ही बाजार गया था जहां से वापस अपने मोटर सायकल टीव्हीएस क्रमांक सीजी-28 एन-0343 से रात्रि करीबन 8 बजे अपने गांव साल्हेघोरी पहुंचा मेन रोड़ स्थित भुपेंन्द्र साहू के दुकान के पास पहुंचा था, जहां पर उसके गांव के त्रिभुवन उर्फमोटे, राजू भास्कर, शिवचरण के अलावा अन्य लोग रोड़ में खड़े होकर गाली-गलौज कर रहे थे। तभी प्रार्थी के मोबाईल में फोन आने पर वहीं पर रूककर फोन पर बात करने के लिए मोबाइल निकाला। उसी समय त्रिभुवन उर्फ मोटे अपने साथी राजू भास्कर, शिवचरण के साथ एक राय होकर प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद के पास आकर त्रिभुवन उर्फ मोटे प्रार्थी के मोबाईल फोन को बलपूर्वक छिन लिया, जिसका विरोध करने पर तीनों गालियां देते हुये जान सहित मारने की धमकी देते प्रार्थी को हाथ मुक्का डण्डा से मारपीट किया गया। रिपोर्ट पर धारा 296,115(2),351(2), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 03.09.2025 को प्रकरण के आरोपियों को थाना चिल्फी लाकर मामले का प्रार्थी लक्ष्मी प्रसाद साहू से आरोपियों की पहचान कराया गया।

एकलशिक्षकीय विद्यालय भैंसामुड़ा में नियुक्त हुई शिक्षिका

युक्ति युक्तकरण से अध्यापन व्यवस्था हुई बेहतर

कोरबा । करतला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा में संचालित प्राथमिक शाला आश्रम और प्राथमिक शाला भदरापारा में गाँव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इन विद्यालयों में एकमात्र शिक्षक होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई की राह बहुत कठिन हो गई थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया से स्कूल में अब अन्य शिक्षको की पदस्थापना हो गई है। एकलशिक्षकीय विद्यालय को शिक्षक मिल जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई की राह आसान होने के साथ ही उनका भविष्य भी उज्ज्वल नजर आने लगा है। शासन द्वारा अपनाई गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया से जिले के अतिशेष शिक्षको को रिक्त और आवश्यकता वाले विद्यालयों में पदस्थ किया गया है। इस प्रक्रिया से करतला ब्लॉक के अंतर्गत भैसामुड़ा के प्राथमिक शाला आश्रम स्कूल में शिक्षिका श्रीमती सुमित कँवर की नियुक्ति हुई है। विद्यालय एकलशिक्षकीय था और यहाँ एकमात्र शिक्षक सियाराम कश्यप विद्यार्थियों को अध्यापन कराते हैं। अब यहाँ शिक्षिका पदस्थ हो जाने के बाद उन्हें भी राहत मिली है। विद्यालय में पढाई करने वाली गौरी,देवंती, पूर्वी का कहना है कि मैडम नई आई हैं। वह हम लोग को पढ़ाती हैं। शिक्षिका सुमित कँवर ने बताया कि विद्यालय में 29 बच्चे हैं। यहाँ पदस्थ होने के बाद नियमित क्लास आती हैं और पढ़ाती हैं। इसी गाँव के भदरापारा में भी एक अन्य प्राथमिक शाला संचालित है। यहाँ 14 बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्यालय की प्रधान पाठिका श्रीमती रंभा मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2021-22 से यह विद्यालय एकलशिक्षकीय था। हमारे विद्यालय में सुभद्रा पाल युक्ति युक्तकरण से शिक्षिका के रूप में पदस्थ हुई है। विद्यालय के विद्यार्थी जानसी, विनय,आर्यन, वीरा ने बताया कि नई मैडम सुभद्रा पाल आई हैं, वह कक्षा लेती हैं।

पुल में जाम की स्थिति से परेशानी, राताखार तिराहा पर बनेगा नया पुल

कोरबा, संवाददाता।

शहर के विस्तार, लोगों की आवश्यकता, क्रयशक्ति में बढ़ोत्तरी के साथ वाहनों की संख्या में इजाफे से कुल मिलाकर सडकों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि कोरबा के मुख्य मार्ग पर पीएच रोड स्थित नहर पुल में जाम के कारण अक्सर परेशानी उत्पन्न हो रही है। इसका हल निकालने के लिए राताखार तिराहा पर नहर में अतिरिक्त पुल को विकल्प बनाया गया है। इसके लिए घोषणा हो गई है। नगर निगम जल्द इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार को भेजेगा। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पुल के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करने की घोषणा की। स्थानीय विधायक व केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसका प्रस्ताव रखा था। शहर में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण पीएच रोड नहर पुल पर लंबे समय से समस्याएं हैं। इस वजह से आम दिनों के साथ-साथ त्योहारी सीजन में इस रास्ते पर घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। स्टेशन, बस स्टैंड जाने वाले लोगों को जहां परेशान होना पड़ता है वहीं दूसरे रास्तों से आने वाली एंबुलेंस, मुक्तांजलि वाहन और अन्य महत्वपूर्ण गाडियों के मौके पर फंसने से चिंता बढ़ जाती है कि आगे क्या होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समस्या का हल निकालना जरूरी हो गया। कई स्तर पर पहल होने से प्रशासन और नगर निगम ने प्रभावी तौर पर आगे काम करने की जरूरत बताई।

जानकारी मिली है कि मौजूदा नहर पुल से होकर राताखार की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग में तिराहे से होकर नहर के दूसरी तरफ अतिरिक्त पुल का निर्माण कराया जाना है। इसी पर 9 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। दूसरे हिस्से की सडक इसमें कनेक्ट होने से ट्रैफिक के दबाव को कम किया जाना संभव होगा। लोगों को अपनी जरूरत के लिए नया विकल्प जल्द मिले, इसकी कोशिश होगी।

फेस्टिवल सीजन : नवरात्र पर्व शुरू होने के पहले ट्रैफिक नियंत्रण पर काम

कोरबा, संवाददाता।

फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होने में अभी देर है लेकिन इससे पहले ही कोरबा क्षेत्र में भीड़भाड़ की स्थिति बन रही है। इसके कारण ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस को जुटना पड़ा है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम यहां वहां नजर आ रही है जिस पर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में अपनी भूमिका निभाना का जिम्मा है। उपलब्ध संसाधनों के साथ लगातार ऐसे मामलों में नजर रखने के साथ गड़बड़ी दिखाई देने पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने वाहन चालकों को पहले से ही निर्देशित कर रखा है कि वह हर हाल में उचित स्थान पर ही पार्किंग करें। उनकी ओर से ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिसके कारण व्यवस्था बाधित हो और फिर जाम जैसी स्थिति निर्मित हो। इसके लिए विभिन्न पॉइंट पर विशेष मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कार्रवाई भी।

बताया गया कि नवरात्र पर्व शुरू होने से पहले ही शहरी क्षेत्र में यातायात से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए काम होगा। जिन क्षेत्रों में क्राउड्स कुछ ज्यादा होता है वहां पर पुलिस की टीम ड्यूटी करेगी। उद्देश्य है कि ऐसा करने से ना केवल व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए बल्कि भीड़भाड़ के दौरान अराजक तत्वों के द्वारा की जाने वाली घटनाओं पर ब्रेक लगाया जा सके।

अब तक सैकड़ों मामलों में कार्रवाई। बताया गया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दुपहिया पर तीन सवारी के साथ प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने, मॉडिफाई साइलेंसर लगाने, बड़ी गाडियों में ब्लैक फिल्म और रेडियम पट्टी ना होने पर भी संज्ञान लिया जा रहा है। अब तक ऐसे सैकड़ो मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया गया कि शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर धारा 185 के अंतर्गत चालकों के खिलाफमामले बनाए गए हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने कहा कि यह अभियान सतत रूप से जारी रखा जाएगा।

नगर निगम की कोरबा को गजब की सौगात

कोरबा लोकशक्ति।

नगर पालिका निगम कोरबा अपने विवादित फैसलों को लेकर जन सामान्य के बीच सरगम चर्चा का विषय बन गया है। शुक्रवार को सिटी कोतवाली के निकट सब्जी बेचने वाले गरीब ग्रामीण कोई यातायात में बाधक बता कर बलपूर्वक हटा दिया गया। इसके बाद नगर निगम कोरबा एक बार फिर जन चर्चा का विषय बन गया।

आपको बता दें कि सिटी कोतवाली के सामने सड़क के किनारे किनारे प्रतिदिन सुबह आसपास के ग्रामों के ग्रामीण वर्षों से छोटी-छोटी सब्जियों की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे हैं लेकिन नगर पालिका निगम कोरबा को यह बात रास नहीं आई। शुक्रवार को नगर निगम कोरबा का अमला सुबह-सुबह जेसीबी लेकर दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और गरीब सब्जी विक्रेताओं को अपनी दुकान हटाने के लिए बाध्य कर दिया गया। इससे पहले भी नगर निगम कोरबा इन सब्जी विक्रेताओं को प्रताड़ित कर चुका है। कुछ समय पहले ही नगर निगम के कारिंदों ने यहां दुकान लगा कर बैठे छोटे-छोटे सब्जी विक्रेताओं को उनकी सारी सब्जियां जप्त कर मौके से हटा दिया था। इसी दिन नगर पालिका निगम कोरबा की आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने कोऑपरेटिव बैंक के पास फ्लप के ठेले लगाकर जीवन यापन करने वाले छोटे-छोटे दुकानदारों के ठेले हटाने के साथ ही सीतामढ़ी से लेकर पुराने बस स्टैंड तक सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को बेदखली का फरमान सुना दिया था। इसके साथ ही गीतांजलि भवन में आम लोगों के आवागमन के लिए बनाई गई गैलरी पर अवैध कब्जा कर दुकान सजाने वाले दुकानदारों को अवैध कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कुछ लोगों को दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को तोड़कर हटाने का भी नोटिस जारी किया गया था। लेकिन रसूखदार दुकानदारों ने अपना भेजो कब्जा नहीं हटाया और नगर निगम आयुक्त उनके खिलाफ नीम अनुसार कोई भी कार्रवाई करने में समर्थ और असफल सिद्ध हो गए। परंतु फ्लप के चले लगाने वाले छोटे-छोटे व्यापारी दोबारा अपनी जगह पर ठेले नहीं लगा पाए बल्कि उसे स्थान पर सौंदर्यीकरण के नाम पर स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है।

खेद की बात तो यह है कि सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले और फ्लप का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले छोटे-छोटे व्यापारियों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं दी गई है। लोगों का कहना है कि इन छोटे कारोबारियों को यातायात सुगम बनाने की दृष्टि से हटाया भी गया है तो कम से कम उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान निर्धारित कर जानकारी देना चाहिए, जहां पर वह दुकान लगाकर अपना भरण पोषण कर सकें। लेकिन नगर पालिका निगम कोरबा के अफसरों को इन गरीबों की कोई चिंता नहीं है।

असर की बात तो यह भी है की ट्रांसपोर्ट नगर चैक से लेकर शुभदा काम्प्लेक्स, हीरो होंडा एजेंसी, पाम मॉल, शारदा विहार रेलवे क्रासिंग से सुनालिया ज्वेलर्स तक सड़क पर दुकानदार 10 से 20 फीट तक बेजाकब्जा कर लेते हैं, मगर इन पूंजीपतियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नगर निगम बलवान अफसरों की नहीं होती। इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नगर निगम के साहबों की इन प्रभावशाली पैसे वालों से सांठगांठ हो? कुल मिलाकर नगर निगम की कार्रवाई की हर निष्पक्ष व्यक्ति निंदा कर रहा है। आम लोग कह रहे हैं- गरीबों के पेट में लात, अमीरों के कंधे में हाथय नगर निगम की कोरबा को गजब की सौगात.!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन से आरंभ होगा भाजपा का सेवा पखवाड़ा - वेदप्रकाश पाण्डेय

जगदलपुर । भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन 17 सितम्बर से राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आरंभ किया जायेगा। जिसकी तैयारियों व कार्ययोजना को लेकर भाजपा जिले के सभी तेरह मण्डलों में मण्डलवार कार्यशाला आयोजित कर रही है। बुधवार को भाजपा जिला कार्यालय में जगदलपुर पूर्वी मण्डल और जगदलपुर पश्चिम मण्डल की कार्यशाला संपन्न हुई। जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को संपूर्ण समर्पण भाव से सेवा पखवाड़ा में सक्रियता से कार्य करने कहा गया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुये भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने कहा कि सेवा पखवाड़ा 17 सितम्बर से आरम्भ होकर 2 अक्टूबर गाँधी जयंती तक मनाया जायेगा। भाजपा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा में अपना योगदान सुनिश्चित करना है।

प्रदेश कार्य समिति सदस्य विद्याशरण तिवारी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के सभी कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुँच कर कार्यरूप देना है। बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जाना है। पूर्व जिला अध्यक्ष रूप सिंह मण्डावी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में वृक्षारोपण, संगोष्ठी आदि कार्यक्रमों की रुपरेखा बनी है। प्रत्येक कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। महापौर संजय पाण्डेय ने कहा कि शक्ति केन्द्र प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्ष, सचिव, बूथ स्तर के एक एक कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा करें। आमजन का सहयोग लेकर जोड़ने का प्रयास करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिमी मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा व पूर्वी मण्डल अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने की। कार्यशाला का संचालन दिगम्बर राव, संजय चंद्राकर एवं आभार प्रदर्शन विक्रम सिंह यादव, शशिनाथ पाठक ने किया।

पशु तस्करी के मामले में फरार आरोपी ओडिसा से गिरफ्तार

बिलासपुर। जिले की थाना रतनपुर पुलिस ने पशु तस्करी के एक मामले में फरार आरोपी को ओडिशा के कोमना क्षेत्र जिला नुआपाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहन स्वामी के कब्जे से पशु तस्करी में उपयोग में लाये जाने वाले 03 वाहनों को जप्त किया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की पतातलाश जारी है।

बता दें कि दिनांक 10.09.2025 को थाना रतनपुर में जरिये मोबाईल से सूचना मिला कि रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग से रतनपुर की ओर आ रही आयशर वाहन में बिना चारा पानी के मवेशियों को ठूंस ठूंसकर भरकर कत्लखाना उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहा है, कि सूचना पर पूर्व में रेड कार्यवाही कर करने पर कुल 17 नग मवेशी जिसमें 02 नग भैंसा मृत अवस्था में कीमती करीबन 595000 रूपये, 01 आयशर वाहन क्रमांक सीजी 04 पीटी 8078 को जप्त कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (आईपीएस)के द्वारा मामले में इण्ड-टू-इण्ड कार्यवाही करने हेतु निदेर्शित करने पर मामले संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की लगातार पता तलाश की जा रही है। आरोपियों की पता तलाश दौरान पूर्व में जप्त वाहन के वाहन स्वामी के द्वारा अपनी वाहन का प्रयोग पशु तस्करी में किये जाने तथा छत्तीसगढ़ से उत्तरप्रदेश व ओडिशा के बुचड़खानों में पशुओं को उक्त आरोपी के वाहन में पहुँचाये जाने की सूचना पर आरोपियों की थाना रतनपुर पुलिस टीम द्वारा लगातार पतातलाश की जा रही थी।

मनोरंजन के साथ ही कार्टून समाज को जागरूक करने वाली कला भी: सीएम साय

रायपुर। कार्टून मनोरंजन के साथ-साथ समाज को नसीहत देने वाली कला भी है - मुख्यमंत्री श्री सायकार्टून मनोरंजन के साथ-साथ समाज को नसीहत देने वाली कला भी है - मुख्यमंत्री श्री साय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल-2025 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कार्टून केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण भी है, जो हास्य और व्यंग्य के माध्यम से गंभीर मुद्दों को सरलता से प्रस्तुत करता है। कार्टून मनोरंजन के साथ ही समाज को जागरूक करने और सोचने के लिए प्रेरित करने वाली कला है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जम्मू-कश्मीर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट श्री मनोज चोपड़ा को कार्टून वॉच पत्रिका का लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड प्रदान किया। उन्होंने कार्टून फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे कार्टूनिस्टों का उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं भी कार्टून बनाया।कार्टून वॉच फेस्टिवल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह गर्व की बात है कि कार्टून वॉच पत्रिका ने 29 वर्षों का सफल सफर तय कर लिया है और अब अपने 30वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। मैं कार्टून वॉच की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे आगे भी कार्टून की इस विधा में उत्कृष्ट कार्य करते रहें।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यदि अगले वर्ष कार्टून वॉच फेस्टिवल बस्तर में आयोजित हो तो यह अत्यंत हर्ष का विषय होगा। बस्तर में अब शांति स्थापित हो रही है और जल्द ही यह क्षेत्र पूर्णतः नक्सलमुक्त होगा। नियद नेल्ला नार योजना (जिसका अर्थ है ङ्क आपका अच्छा गाँव) के माध्यम से सरकार की योजनाएँ बस्तर के लोगों तक पहुँच रही हैं। 300 से अधिक गाँवों में अब तक सड़क, बिजली, पानी और राशन कार्ड जैसी सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। जहाँ पहले बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहाँ अब स्कूल की घंटी बज रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसी तरह बस्तर की सांस्कृतिक पहचान का उत्सव बस्तर पंडुम आयोजित किया गया, जिसमें 47 हजार लोग शामिल हुए। यह इस बात का प्रमाण है कि बस्तर के लोग अब मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। कल ही मैं बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुआ। अब बस्तर में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप के रूप में हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सेंटर और टेक्सटाइल सहित अनेक क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। हाल ही में जापान और कोरिया की यात्रा के दौरान भी हमने उद्योगों के साथ कई एमओयू किए हैं।

भू-अर्जन की कार्यवाहियों में लाएं तेजी

उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, अगली बैठक के पहले भू-अर्जन, प्राक्कलन, निविदा, कार्य अनुबंध व कार्यादेश संबंधी सभी कार्यवाहियों को पूर्ण करने कहा सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, बरसात के तुरंत बाद युद्धस्तर पर करें सड़कों की मरम्मत

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित बैठक में शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त सड़क निर्माण के कार्यों के लिए जरूरी भू-अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर के साथ मिलकर त्वरित कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही उन्हें निर्धारित समय पर पूरा करने पर जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

भू-अर्जन की कार्यवाहियों में लाएं तेजी ङ्क श्री अरुण साव : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़क, सेतु और भवन निर्माण की सभी परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फील्ड में सक्रियता व गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों में तेजी से भू-अर्जन कर निविदा की कार्यवाही पूर्ण करने और यथाशीघ्र कार्यारंभ करने को कहा।

भू-अर्जन की कार्यवाहियों में लाएं तेजी अरुण साव : उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में मौजूद सेतु बंध तथा सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करते हुए प्रस्तावित कार्यों के लिए जरूरी मंजूरी तत्परता से प्रदान करें। उन्होंने डीपीआर बनाते समय ही परियोजना का अच्छे से मूल्यांकन करने को कहा ताकि बजट और कार्य पूर्णता के लिए निर्धारित समय के पुनरीक्षण की जरूरत न पड़े। उन्होंने बरसात के तुरंत बाद प्रदेशभर में सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिसम्बर तक सभी जिलों में मरम्मत का काम पूर्ण करने को कहा। श्री साव ने सभी मुख्य अभियंताओं को अगली समीक्षा बैठक के पहले भू-अर्जन, प्राक्कलन, निविदा, कार्य अनुबंध और कार्यादेश से संबंधित सभी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में सड़कों पर पेच रिपेयर के लिए कार्ययोजना के अनुसार अनुबंध एवं कार्यादेश की स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा ए.डी.बी. के अपूर्ण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की।

गौ विज्ञान परीक्षा 2025 का किया जायेगा आयोजन

सूरजपुर प्रेमनगर । छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा शिक्षा जगत में नवाचार और विद्यार्थियों तथा समाज को गौ माता का संरक्षण संवर्धन पालन एवं आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक महत्व को जानने तथा संस्कारों की नई दिशा तय करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय /अशासकीय विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा छठवीं से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए गौ विज्ञान परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा के सफल संचालन एवं आयोजन हेतु प्रेम नगर विकासखंड नोडल अधिकारी श्री श्रवण कुमार साहू एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री मुकेश चंद्र भारद्वाज के द्वारा विकासखंड के समस्त हाई / हायर सेकेंडरी स्कूल तथा माध्यमिक शालाओं का दौरा किया जा रहा है एवं शत प्रतिशत बच्चों का पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय स्तर पर परीक्षा प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 11.9.2025 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेम नगर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय प्रेम नगर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सीबीएसई इंग्लिश मीडियम करमीटीकरा प्रेम नगर का दौरा किया गया एवं परीक्षा प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ,सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी,शिक्षा समिति के पदाधिकारी अन्य अधिकारीयों तथा समस्त संकुल समन्वयकों की बैठक आयोजित की गई।

आर्थिक मदद से बढ़ा आत्मविश्वास, अश्वनी ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना ज़रूरतमंद श्रमिक परिवार की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस योजना का लाभ रायपुर ज़िले के आरंग ब्लॉक के ग्राम पचेड़ा की निवासी श्रीमती अश्वनी जांगड़े श्रमिक का काम करती थी 7 इस योजना के तहत 20 हजार की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई जिससे उन्हें बड़ी मदद मिली।

60 वर्षीय श्रीमती जांगड़े ने कहा, मैंने अपना पैसा घर के काम व तीर्थ यात्रा में उपयोग किया एवं कुछ पैसे अपने भविष्य के सुरक्षित रखी हूं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना हम श्रमिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न केवल हमें आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।

श्रीमती अश्वनी जांगड़े ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन श्रमिकों के हित में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों को संबल मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। उप मुख्यमंत्रीद्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आज आयोजित बैठक में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर ओलंपिक का वृहद आयोजन करने इसकी रुपरेखा और व्यवस्थागत तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। आगामी अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले बस्तर ओलंपिक में तीन स्तरों विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बस्तर संभाग के सातों जिलों और 32 विकासखंडों के 40 हजार से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव श्री सुखनाथ अहिरवार और संचालक श्रीमती तनूजा सलाम भी बैठक में शामिल हुईं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेलों का आयोजन नहीं है, बल्कि विकास और खेल का संगम है। यह संगठित रूप से बस्तर के युवाओं के सशक्तीकरण और उनमें नेतृत्व के विकास की पहल है। राज्य सरकार इन रचनात्मक पहलों से बस्तर में भयमुक्त वातावरण बनाकर युवाओं को खेल और उत्सव से जोड़ना चाहती है। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर पुख्ता कार्ययोजना तैयार करते हुए आयोजन के ध्येय वाक्य 'करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर' (खेलेगा बस्तर जीतेगा बस्तर) को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। श्री साव ने यूथ आइकॉन घोषित किए गए पिछले वर्ष के विजेता खिलाड़ियों, बस्तर संभाग के सभी खेल अधिकारियों, पी.टी.आई., पंचायत सचिवों, 'बिहान' की महिलाओं और खेल संघों को सक्रियता से जोड़कर बस्तर ओलंपिक को जन-जन तक पहुंचाने को कहा। उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बैठक में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों से कहा कि बस्तर ओलंपिक को यादगार बनाने सभी विभाग अपनी-अपनी भूमिका और कार्यों के अनुरूप जिम्मेदारियों का वहन करें। बस्तर के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और सकारात्मक वातावरण तैयार करेगी। उन्होंने बस्तर ओलंपिक के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए इसमें बस्तर के सभी गांवों के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चत करने को कहा। श्री शर्मा ने आयोजन की तैयारियों को मूर्त रूप देने जल्दी ही इससे जुड़े विभागों, अधिकारियों और संस्थाओं की बस्तर में भी बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए जिससे की तैयारियों को और गति दी जा सके। विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले बस्तर ओलंपिक में 11 खेलों को शामिल किया गया है। जूनियर वर्ग में बालक और बालिकाओं तथा सीनियर वर्ग में महिला और पुरूषों के लिए प्रतियोगिताएं होंगी। नक्सल हिंसा के दिव्यांगों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी संभाग स्तर पर पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बस्तर ओलंपिक के दौरान एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साखींच में पूरे बस्तर के खिलाड़ी अपना खेल कौशल दिखाएंगे।

जीएसटी अब गुड एंड सिंपल टैक्स - मुख्यमंत्री साय

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी पर बात करते हुए कहा कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों और बड़े व्यापारियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का मतलब अब गुड एंड सिंपल टैक्स है।सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, यह हमारा सौभाग्य है। 2014 के पहले हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से अस्थिर थी। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही दिन-रात देश के लिए सोचकर, पिछले दस वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में हमारे देश को दसवें स्थान से पांचवे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पांचवे से चौथे स्थान पर देश को लेकर आए और अब जीएसटी रिफॉर्म लाकर तीसरे स्थान पर लाने के लिए तैयार हैं।श्री साय ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा। उन्होंने कहा कि सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ होगा,जबकि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जीएसटी परिषद ने एक व्यापक सुधार पैकेज की अनुशंसा की है जिसमें सरलीकृत दो-स्लैब संरचना (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) के साथ दर युक्तिकरण, आम आदमी, श्रम-केंद्रित उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेक्टरों में दरों में कटौती शामिल है। ये अनुशंसाएं जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों के बीच जीएसटी को सरल, निष्पक्ष और अधिक विकास-उन्मुख बनाने के लिए आम सहमति पर आधारित हैं। संशोधित दरें और छूट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जिससे आम आदमी, परिवारों, किसानों और व्यवसायों के लिए समय पर राहत सुनिश्चित होगी। केवल निर्दिष्ट सामान जैसे सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी अपवाद होंगे, जिनके लिए जीएसटी और मुआवजा उपकर की विद्यमान दरें लागू रहेंगी और नई दरें बाद की तिथि में लागू की जाएंगी।

केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव

नवोदय एवं एकलव्य विद्यालयों में खेलों पर विशेष फोकस करने तथा प्रशिक्षकों की कोचिंग स्किल अपडेट करने का दिया सुझाव

रायपुर। नवोदय एवं एकलव्य विद्यालयों में खेलों पर विशेष फोकस करने तथा प्रशिक्षकों की कोचिंग स्किल अपडेट करने का दिया सुझाव उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव आज केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बैठक में खेल एवं युवा विकास से संबंधित चुनौतियों व अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री साव अपने प्रवास के दौरान मुंगेली कलेक्टोरेट से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। बैठक में युवाओं को खेलों से जोड़ने और देश में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए 'खेलो इंडिया' योजना की तर्ज पर नई युवा कल्याण योजना शुरू करने पर चर्चा की गई। साथ ही हर राज्य में खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना, खेल प्राधिकरण ऑफइंडिया के क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, खेल अधोसंरचनाओं के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए विशेष बजट प्रावधान, एकीकृत डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के विकास जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के स्कूलों में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे विकसित करने तथा आवश्यक स्टॉफ की भर्ती करने का सुझाव दिया। उन्होंने नवोदय एवं एकलव्य विद्यालयों में भी खेलों पर विशेष फोकस करते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे ले जाने की जरूरत बताई। उन्होंने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में नियमित खेल गतिविधियां संचालित करने विशेष कार्ययोजना तैयार करने की भी बात कही। श्री साव ने बैठक में ''साइ'' (स्ढ्ढ) के रीजनल सेंटर्स में खेल प्रशिक्षकों की कोचिंग स्किल तथा उनके ज्ञान एवं कौशल के उन्नयन का भी सुझाव दिया। उन्होंने खेल कोटे से शासकीय सेवाओं में नियुक्त खिलाड़ियों को अन्य कार्यों में संलग्न न कर केवल खेल से जुड़ी जिम्मेदारियां देने पर जोर दिया ताकि उभरते खिलाड़ियों को उनके अनुभवों का लाभ मिल सके।

भाजपा बस्तर मंडल ने किया सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यशाला आयोजित

बस्तर । भारतीय जनता पार्टी बस्तर मंडल ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की।भारतीय जनता पार्टी बस्तर मंडल द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की कार्यशाला में प्रभारी विजय पाण्डेय ने कार्यकर्ताओं को सेवा पखवाड़ा के उद्देश्य और इसकी रूपरेखा से अवगत कराया।यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें समाज सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा। मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडावी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा प्रदान करना और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करेगी। इससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा और वे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे।इस अवसर पर भाजपा बस्तर मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडावी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामानंद मिश्रा ,बस्तर मंडल प्रभारी विजय पाण्डेय, मंडल उपाध्यक्ष दयाराम बघेल ,मंडल महामंत्री हेमराज कश्यप, चमरू यादव ,मंडल मंत्री सुष्मिता मिस्त्री, बसंती पटेल, जनपद उपाध्यक्ष जयबती बघेल,अनिल जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप जिला पंचायत सदस्य शंकुतला कश्यप, पूर्व बस्तर जनपद उपाध्यक्ष मोहन मौर्य, पूर्व जनपद सदस्य फुलसिंग मौर्य ,नगर पंचायत बस्तर नेता प्रतिपक्ष समीर कुमार मिश्रा,विरसिंह मौर्य, बंशी कश्यप,मंगल बघेल, अनिता बघेल, जनपद सदस्य निलेन्द्री बघेल,गणेश बघेल,योगेश चंदेल सहित अन्य भाजपा कार्यकता उपस्थित थे।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। **संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।**
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily **कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल** (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)